RNI NO.- CHHHIN/2023/87391

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

अंक-05 | वर्ष-3 | माह-अगस्त 2025 | प्रकाशन तिथि- अगस्त 2025 | रायपुर से प्रकाशित | पृष्ठ-40 | मूल्य-11/-

79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन

ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विकसित भारत तक का संकल्प

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

भारतीय सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम
की संयुक्त विशेष भर्ती योजना

"बीमा सखी" महिला बीमा अभिकर्ता

3 वर्ष तक प्रतिमाह मानदेय

- 1st Year Rs. 7000 P.M.
- 2nd Year Rs. 6000 P.M.
- 3rd Year Rs. 5000 P.M.

साथ ही आकर्षक अतिरिक्त कमीशन

बीमा सखी के अन्य लाभ

पार्ट टाईम/फूल टाइम कार्य
ग्रुप बीमा, होम लोन इत्यादि

आवश्यक शर्तें : 10 वीं पास उम्र 18 वर्ष से अधिक

एलआईसी महिला विशेष भर्ती

महिला कैरियर एजेंट के रूप में
एलआईसी से जुड़ें

Years	RS
1st	Rs. 7000/-
2nd	Rs. 6000/-
3rd	Rs. 5000/-

B.V.S.Rajkumar
{OVER FOUR DECADES OF EXPERIENCE}
L.I.C.OF INDIA, RAIPUR

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

98266-38002

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ से प्रकाशित एक सम्पूर्ण पत्रिका

प्रधान संपादकः

जी. भूषण राव

समाचार संपादकः

जी.वी.एस. रूक्मणि देवी

उप संपादकः

राखी श्रीवास्तव

सलाहकार संपादकः

रविश बेंजामिन

अशोक तोमर

मार्केटिंग हेडः

शैलेन्द्र दवे

मार्केटिंग प्रतिनिधिः

हरिमोहन तिवारी

आवरण सज्जाः

Infinity

ब्यूरो हेडः

बिलासपुरः विनीत चौहान

जशपुरः आनंद गुप्ता

कोरियाः प्रवीण निशी

बस्तरः सुनील सिंह राठौर

आफिसः

बी-13, बसंत पार्क

अनमोल सुपर मार्केट के पास

महावीर नगर, न्यू पुरेना रायपुर छ.ग.

ईमेलः swatantrachhattisgarh@gmail.com

वेबसाईटः www.swatantrachhattisgarh.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

जी. भूषण राव द्वारा सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती रायपुर द्वारा मुद्रित एवं बी-13, बसंत पार्क, अनमोल सुपर मार्केट के पास, महावीर नगर, न्यू पुरेना, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित

मो.:- 99934-54909

संपादकः जी. भूषण राव

पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखकों के अपने विचार है, किसी भी विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्र रायपुर होगा।

वार्षिक सदस्यता शुल्क सभी (विशेषांकों सहित प्रस्तावित) 132/-रू.मात्र

Pg 3

79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विकसित भारत तक का संकल्प

Pg 5

छत्तीसगढ़ की बहनों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्ति करण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री

Pg 10

बदलते बस्तर की तस्वीर - तिरंगे के साथ नई सुबह

Pg 18

महतारी वंदन योजना से रक्षाबंधन की खुशियाँ हुईं दुगनी...

Pg 22

कृष्ण जन्माष्टमी- भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का पावन उत्सव

जीएसटी सुधारों की नई राह और दूसरी दिवाली का वादा

लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह घोषणा कि देश की जीएसटी व्यवस्था को अब केवल दो स्लैब–5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत–में सीमित किया जाएगा, निस्संदेह एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक संदेश है। प्रधानमंत्री ने इसे **दूसरी दिवाली** करार देते हुए जनता को यह भरोसा दिलाया कि कर प्रणाली सरल होगी और उपभोक्ताओं से लेकर उद्योग जगत तक सभी को राहत मिलेगी। जीएसटी लागू हुए सात साल हो चुके हैं। शुरुआत में ही इसके कई स्लैब– 0%, 5%, 12%, 18% और 28% - ने आम उपभोक्ता और कारोबारी वर्ग के लिए उलझन पैदा की थी। छोटे कारोबारियों को बार-बार बदलते नियमों और जटिल रिटर्न फाइलिंग की समस्याओं से जूझना पड़ा। ऐसे में कर ढांचे का सरलीकरण लंबे समय से अपेक्षित था। अब अगर केवल दो दरें लागू होती हैं तो न केवल कारोबारियों का बोझ घटेगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी दामों में अधिक स्पष्टता मिलेगी। इस फैसले से सरकार को राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। दीपावली जैसे त्योहार से पहले राहत पैकेज की तरह आई यह घोषणा सीधा मध्यमवर्ग और व्यापारियों को आकर्षित करेगी। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** केवल नारे तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तविक सुधारों के जरिए जनता तक पहुँचाया जाएगा। हालाँकि, चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। कर संग्रह में संतुलन बनाना सबसे बड़ी परीक्षा होगी। 28 प्रतिशत वाले उच्च कर वर्ग को खत्म करने से लग्ज़री और सिन टैक्स से मिलने वाला राजस्व घट सकता है। इसका विकल्प खोजने की ज़िम्मेदारी केंद्र और राज्यों दोनों पर होगी, क्योंकि जीएसटी परिषद एक साझा मंच है। यदि राज्यों को पर्याप्त मुआवज़ा न मिला तो वे इस बदलाव पर सहमति देने में हिचक सकते हैं। इसके बावजूद यह कदम सही दिशा में है। एकरूप कर संरचना से न केवल कर चोरी की संभावनाएँ घटेंगी बल्कि **एक राष्ट्र, एक बाजार** की परिकल्पना और मजबूत होगी। उपभोक्ता को अब यह सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि किस वस्तु पर 12% है और किस पर 18%। सरल और पारदर्शी प्रणाली जनता के मन में कराधान के प्रति भरोसा बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री का दूसरी दिवाली का वादा केवल प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए। यदि यह सुधार समयबद्ध तरीके से लागू होते हैं, और व्यापारियों को तकनीकी व प्रशासनिक सहयोग दिया जाता है, तो वास्तव में अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा। कुल मिलाकर, यह घोषणा सिर्फ एक चुनावी तुकबंदी नहीं, बल्कि कर सुधारों के लंबे सफर में एक अहम पड़ाव है। अब निगाहें जीएसटी परिषद और राज्यों के रुख पर होंगी। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो सचमुच इस दीपावली पर जनता को एक अतिरिक्त उत्सव मनाने का अवसर मिलेगा–एक सरल, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी कर व्यवस्था के रूप में।

आपका अपना
भूषण राव

79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन
ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विकसित भारत तक का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। यह उनका लगातार 12वां संबोधन रहा। पीएम मोदी का भाषण इस बार कई मायनों में खास रहा, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, कल्याणकारी योजनाओं, आत्मनिर्भर भारत, युवाओं और किसानों के सामर्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया।

विकसित भारत का संकल्प– पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमारी प्राथमिकता है। हमने पंचप्रण से जो संकल्प लिए थे, उन्हीं के आधार पर हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। हमारी विरासत हमारी ताकत है और हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

मिशन सुदर्शन चक्र– प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए घोषणा की कि आने वाले 10 वर्षों में मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया जाएगा। यह एक आधुनिक हथियार प्रणाली होगी, जो दुश्मन के हमले को निष्क्रिय करने के साथ कई गुना ज्यादा ताकत से जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम होगी।

डेमोग्राफी मिशन– पीएम मोदी ने डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर चिंता जताई और कहा कि देश में घुसपैठिए युवाओं की रोज़ी-रोटी छीन रहे हैं और आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके समाधान के लिए सरकार हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करेगी।

नक्सलवाद पर कड़ी चोट– पीएम मोदी ने कहा कि कभी नक्सलवाद 125 से ज्यादा जिलों तक फैला हुआ था, लेकिन आज यह सिर्फ 20 जिलों तक सीमित रह गया है। बस्तर, जो नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, आज वहां से युवा ओलंपिक तक पहुंच रहे हैं।

युवाओं के लिए 'प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना'- देश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लॉन्च की। इसके तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी और नई नौकरियां देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे करीब 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ होगा।

आर्थिक सुधार और कर छूट– पीएम मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आज मजबूत स्थिति में है। उन्होंने नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी और इनकम टैक्स सुधार की घोषणा की। पीएम मोदी ने बताया कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स शून्य रहेगा।

किसानों और ग्रामीण भारत पर फोकस– पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के खिलाफ किसी भी नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत आज दूध और दाल उत्पादन में नंबर वन और मछली उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। पिछले वर्ष 4 लाख करोड़ रुपये का एग्रो-प्रोडक्ट निर्यात हुआ।

आत्मनिर्भर भारत और स्पेस मिशन– प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने दम पर स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा,

चाहे वह फर्टिलाइज़र, ईवी बैटरी, मेड इन इंडिया जेट इंजन या सेमीकंडक्टर क्यों न हो।

ऊर्जा और पर्यावरण– पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने 2030 तक का 50प्रतिशत क्लीन एनर्जी लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी पर भी तेजी से काम कर रहा है।

अन्य प्रमुख बातें

- पीएम मोदी ने मोटापे को देश के लिए नई स्वास्थ्य चुनौती बताया।
- धारा 370 हटाने को एक देश, एक संविधान का प्रतीक बताया।
- संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी और संविधान को देश का मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ बताया।
- ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जांबाज सैनिकों को सलामी दी।
- पाकिस्तान पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब सहन नहीं किया जाएगा।

पीएम मोदी का यह 82 मिनट का भाषण भविष्य की रूपरेखा, सुरक्षा रणनीति, आर्थिक सुधार, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक रहा।

छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति- हर घर बनेगा बिजलीघर

छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उनकी यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत विकास के बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करेगी। साथ ही जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्यों में योगदान सुनिश्चित होगा।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में घर-घर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर लोगों को प्रदूषण मुक्त, मुफ्त और निरंतर बिजली देने की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से प्रत्येक उपभोक्ता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर उनके मासिक खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

हर नागरिक की होगी भागीदारी

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्रता रखने वाले सभी नागरिक जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन और उपयुक्त छत है, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि योजना के अंतर्गत एक बार सोलर पैनल स्थापित होने के बाद उपभोक्ता को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे न सिर्फ बिजली बिलों का झंझट समाप्त होगा, बल्कि यदि आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होता है, तो उसे ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी ली जा सकती है।

मिलेगी डबल सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट तक के सौर संयंत्र लगाने पर प्रति वॉट 45 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी जा रही है। इसमें राज्य सरकार ने भी अपनी हिस्सेदारी जोड़ दी है, जिससे उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।

स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण

छत्तीसगढ़ सरकार जीरो कार्बन एमिशन नीति को साकार रूप देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 15 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर सरकार ने वर्ष 2047 तक 45 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। यह नीति न केवल वर्तमान, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हरित और सतत भविष्य सुनिश्चित करेगी।

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति से रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगें। इससे सोलर पैनल के निर्माण, स्थापना, रखरखाव आदि जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर बढ़ेगें। वहीं राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।

योजना के फायदे

केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से डबल सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगा। एक बार सौर पैनल की स्थापना के बाद 20-25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। लोगों को निरंतर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा बिजली बेचने से अतिरिक्त आमदनी होगी। साथ ही स्वच्छ, हरित और पर्यावरण हितैषी जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ की बहनों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रक्षाबंधन पर जशपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ- बिहान की 12 दीदियों को ई-रिक्शा का उपहार

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के गृहग्राम बगिया से जशपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया और बिहान योजना से जुड़ी 12 दीदियों को राखी के उपहार स्वरूप ई-रिक्शा प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं स्व-सहायता समूह की महिला श्रीमती गिलसोनिका पाण्डे के ई-रिक्शा में बैठकर बगिया निवास परिसर की यात्रा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह ई-रिक्शा न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इसकी परिचालन लागत भी कम है। इससे महिलाएं स्थानीय परिवहन सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगी। उन्होंने रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की सभी बहनों की सुरक्षा और सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्व-सहायता समूह की बहनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही यह ई-रिक्शा वितरण किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार मोदी की गारंटी को तेजी से लागू कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 18 लाख आवास का कार्य तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही आवास प्लस प्लस योजना के अंतर्गत 5 एकड़ असिंचित भूमि, 2.50 एकड़ सिंचित भूमि, टू-व्हीलर और 15 हजार रुपये मासिक आमदनी वाले पात्र परिवारों को भी लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख बहनों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अटल डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें आगामी पंचायत दिवस पर सभी ग्राम पंचायतों में शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा के लिए रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों के तहत पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल, डिजिटल और नागरिक-केंद्रित बनाया गया है। दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत बस सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी केंद्र, शासकीय नर्सिंग कॉलेज और शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले जाएंगे।

कार्यक्रम में बताया गया कि ई-रिक्शा का संचालन जिले के विभिन्न रूट्स पर महिला संचालकों द्वारा किया जाएगा। फरसाबहार में प्रतिमा भगत फरसाबहार- कन्दईबहार- अमडीहा- तपकरा मार्ग पर, मदनावती लवाकेरा- अमडीहा- पुराईनबंध- समडमा- तपकरा मार्ग पर, राजकुमारी पैंकरा तपकरा- कन्दईबहार- तुबा- फरसाबहार मार्ग पर और उर्मिला भगत खुटगांव- सिंगीबहार- साजबहार- तपकरा मार्ग पर परिचालन करेंगी। इसी तरह, दुलदुला में बिंदेश्वरी देवी कोसा- दुलदुला- विपतपुर- छेरडांड मार्ग पर, पार्वती साय कोसा- दुलदुला- पतराटोली- लोरो- बम्हनी मार्ग पर, संगीता देवी छेरडांड- लोरो- बम्हनी- कस्तुरा मार्ग पर और बिमला देवी छेरडांड- दुलदुला- लोरो- पतराटोली मार्ग पर परिचालन करेंगी। कांसाबेल में गिलसोनिका पाण्डे टांगरगांव- हथगड़ा- कांसाबेल मार्ग पर, तियासो पैंकरा बांसबहार- दोकड़ा- पुसरा- खुंटीटोली- कांसाबेल मार्ग पर, नीता रवानी कटंगखार- दोकड़ा- बन्दरचुंआ- कांसाबेल मार्ग पर और अंगावती बाई देवरी- दोकड़ा- छाताबर- कांसाबेल मार्ग पर ई-रिक्शा का परिचालन करेंगी।

दूरस्थ अंचलों तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य और जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को वित्तीय सेवाएं उनके ही गाँव में सुलभ हों। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाएं न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देती हैं, बल्कि शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भी आधार बनती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जशपुर जिले के बगिया ग्राम में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से जशपुर विकासखंड के ग्राम आरा, पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम कुड़ेकेला (घरजियाबथान) और बगीचा विकासखंड के ग्राम छिछली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 12वें वार्षिक प्रतिवेदन का भी विमोचन किया।

44 हज़ार से अधिक ग्रामीण होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यकम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जशपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के तीन नई शाखाओं के शुरू होने से 23 ग्राम पंचायतों और 48 आश्रित ग्रामों के लगभग 44 हज़ार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन की बचत होगी।

अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से ग्रामीणों को मिलेगी वित्तीय सेवाएं

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि जशपुर जिले की 268 पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से अब तक लगभग 15 करोड़ रुपये का लेन-देन हो चुका है। आगामी पंचायत दिवस तक जिले की सभी पंचायतों में ये सुविधा केंद्र प्रारंभ करने की योजना है। इन केंद्रों से ग्रामीणों को उनके गाँव में ही बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

जशपुर जिले के ग्राम छिछली की सरपंच श्रीमती अनिमा मिंज, आरा के सरपंच श्री मनोज भगत और कुड़ेकेला के सरपंच श्रीमती शशिकांता पैंकरा ने कहा कि नई बैंक शाखाओं से अब उनके क्षेत्र के ग्रामीणों को सभी बैंकिंग सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।

ग्राम पंचायत आरा से वर्चुअली जुड़ी विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने कहा कि बैंक खुलने से हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ सीधे बैंक के माध्यम से हितग्राहियों को मिलेगा।

ग्राम कुड़ेकेला से वर्चुअली जुड़ी विधायक श्रीमती गोमती साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे लोगों में वित्तीय जागरूकता बढ़ी है और अब 3 नए ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में गति आएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। इन 3 नई शाखाओं के खुलने से जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर 30 हो गई है।

पुनौराधाम- माता जानकी के प्राकट्य स्थल का गौरव पुनर्निर्माण

भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों में कुछ स्थल ऐसे हैं, जिनका महत्व केवल एक धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि वे इतिहास, आस्था, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व के केंद्र बिंदु होते हैं। बिहार के सीतामढ़ी ज़िले का पुनौराधाम ऐसा ही एक पावन स्थल है, जिसे जगत जननी माता जानकी की प्राकट्य भूमि माना जाता है। यह वह पवित्र धरती है, जहां माता सीता का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी मर्यादा, त्याग और धैर्य से पूरे विश्व को आदर्श नारीत्व का संदेश दिया। दुर्भाग्य से, लंबे समय तक यह स्थान सरकारी उपेक्षा और अधोसंरचनात्मक कमी के कारण अपने वास्तविक स्वरूप और भव्यता से वंचित रहा। किंतु अब परिस्थितियां बदल रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार की सक्रियता तथा संत समाज के सतत प्रयासों से पुनौराधाम पुनः राष्ट्रीय पटल पर उभर रहा है। इसमें पातेपुर महंत सह पंच निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर, नागा अध्यक्ष और बिहार धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य बाबा विश्वमोहन दास जी महाराज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

बाबा विश्वमोहन दास जी महाराज की निर्णायक भूमिका

बाबा विश्वमोहन दास जी महाराज मिथिलांचल की धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने वाले अग्रणी संतों में गिने जाते हैं। उनका दृष्टिकोण केवल पूजा-पाठ और आध्यात्मिक प्रवचनों तक सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए समर्पित किया है।

पुनौराधाम की उपेक्षा को उन्होंने न केवल देखा, बल्कि इसे दूर करने का संकल्प भी लिया। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी, पर्यटन मंत्री राजू सिंह, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय सहित अनेक राजनीतिक नेताओं से उनकी घनिष्ठता रही है। इसी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक प्रभाव का उपयोग कर उन्होंने पुनौराधाम के विकास की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया।

पातेपुर श्रीरामजानकी मंदिर के बड़े गुरु महंत संत श्रीकांत शरण दास, स्थान के राजपुरोहित आचार्य पंडित देवेंद्र झा तथा रामानन्दी संप्रदाय के अन्य साधु-संत मानते हैं कि यदि बाबा विश्वमोहन दास जी महाराज यह पहल न करते, तो शायद यह कार्य अभी भी अधर में लटका रहता।

अयोध्या से प्रेरणा, सीता जन्मभूमि की पुकार

अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास और आस्था का स्वर्णिम अध्याय है। किंतु इस गौरवमयी क्षण के साथ एक प्रश्न बार-बार उठता रहा—यदि

भगवान राम के जन्मस्थान को उसका गौरव मिल सकता है, तो माता सीता की जन्मभूमि क्यों उपेक्षित रहे?

यह केवल धार्मिक भावनाओं का मामला नहीं था, बल्कि बिहार और मिथिलांचल की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा प्रश्न था। बिहारवासियों को यह सालता रहा कि जिन माता जानकी ने संपूर्ण रामकथा को पूर्णता दी, उनके जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर का अभाव है।

नीतीश कुमार की पहल और सरकारी संकल्प

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रश्न को गंभीरता से लिया और इसे बिहार की अस्मिता के रूप में स्वीकार किया। उनके नेतृत्व में पुनौराधाम माता जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय विकास के लिए करोड़ों रुपये की योजनाओं का शुभारंभ हुआ। इस पहल में मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाओं का निर्माण, बेहतर सड़क संपर्क, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही, स्थानीय रोजगार सृजन और पर्यटन को भी विकास योजना का हिस्सा बनाया गया है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री का भावपूर्ण संदेश

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने पुनौराधाम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा— यह केवल माता जानकी मंदिर निर्माण का कार्य नहीं है, बल्कि इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास का आधारशिला है। यह मिथिलांचल की संस्कृति और गौरव का पुनर्जागरण है। मैं माता जानकी और प्रभु श्रीराम के करोड़ों भक्तों को इस ऐतिहासिक अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मिथिलांचल की संस्कृति भारत की अनन्य और अद्वितीय धरोहर है। इसकी समृद्ध परंपरा, साहित्य, कला और रीति-रिवाज पूरे भारत के लिए गर्व का विषय हैं। पुनौराधाम का विकास इस संस्कृति को और सशक्त करेगा।

पुनौराधाम का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व

पुनौराधाम को सीतामढ़ी का हृदय कहा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और विभिन्न पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, मिथिला के राजा जनक ने यहाँ खेत जोतते समय माता सीता को धरती से प्राप्त किया था। इसीलिए उनका नाम 'सीता' पड़ा। यह स्थान प्राचीन काल से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहां हर साल बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं, विशेषकर विवाह पंचमी और राम नवमी के अवसर पर। किंतु अधोसंरचना के अभाव में श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

सांस्कृतिक धरोहर और मिथिला की पहचान

मिथिलांचल केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक अनूठा रूप है। यहां की मिथिला पेंटिंग, मधुबनी कला, पान और मखाना संस्कृति, मैथिली भाषा और साहित्य—ये सब भारत की सांस्कृतिक संपदा के अनमोल रत्न हैं। माता जानकी इस पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक मातृशक्ति मानी जाती हैं। पुनौराधाम का विकास इन परंपराओं के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पर्यटन और आर्थिक विकास की संभावनाएं

भव्य माता जानकी मंदिर और आसपास के धार्मिक स्थलों के विकास से पुनौराधाम न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल होगा। इससे यहां धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय व्यवसाय—जैसे हस्तशिल्प, मिथिला पेंटिंग, मखाना उत्पाद, होटल-धर्मशालाएं, परिवहन सेवाएं—सभी को लाभ होगा। इससे हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे।

आधुनिक सुविधाओं के साथ आध्यात्मिक वातावरण

पुनौराधाम को विकसित करते समय यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ इसका आध्यात्मिक वातावरण भी सुरक्षित रहे। मंदिर परिसर को पारंपरिक वास्तुकला में बनाया जाएगा, ताकि भक्तों को प्राचीन काल का वही पवित्र अनुभव प्राप्त हो सके। इसके साथ ही, डिजिटल तकनीक का उपयोग कर यहां आगंतुक प्रबंधन, ई-गाइड, ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था और वर्चुअल टूर जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

भविष्य की दिशा

जब अयोध्या का राम मंदिर पूरे विश्व में हिंदू आस्था का केंद्र बन सकता है, तो पुनौराधाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। इसके लिए सरकार, संत समाज और स्थानीय लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। बाबा विश्वमोहन दास जी महाराज और अन्य संतों के मार्गदर्शन में, तथा राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के सहयोग से, पुनौराधाम आने वाले वर्षों में मिथिला और बिहार के गौरव का प्रतीक बनेगा। पुनौराधाम का विकास केवल ईंट-पत्थरों का काम नहीं, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और पहचान का पुनर्निर्माण है। यह उस विरासत को सम्मान देने का प्रयास है, जिसने भारतीय संस्कृति को उसकी गहरी जड़ें दीं।

बाबा विश्वमोहन दास जी महाराज जैसे संतों की निष्ठा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदृष्टि, और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आने वाले समय में पुनौराधाम न केवल भव्य मंदिर का घर होगा, बल्कि यह मिथिलांचल और बिहार के भाग्योदय की नई कहानी भी लिखेगा।

आलेख
राखी श्रीवास्तव

ब्लैकहेड्स ? नो प्रॉब्लम , अब कहें अलविदा, जाने कैसे ?

चेहरे पर ब्लैक हेड्स होना कई लोगों के लिए एक आम स्किन प्रोब्लेम है। ये न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती कम करते हैं, बल्कि मानसिक परेशानी का कारण भी बनते हैं। ब्लैक हेड्स तब बनते हैं जब डेड स्किन सेल्स, अतिरिक्त तेल और गंदगी त्वचा के रोमछिद्रों को बंद कर देते हैं। ये खास तौर पर नाक, ठुड्डी और माथे पर होते हैं। हालांकि मार्केट में इन्हें हटाने के लिए कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, लेकिन प्राकृतिक और घरेलू नुस्खों से इन्हें हमेशा के लिए हटाया जा सकता है। ऐसे में, आइए ला पिएल डर्मेटोलॉजी, मुंबई की त्वचाविज्ञान विशेषज्ञ डॉ. श्रीलता त्रासी से जानते हैं कुछ घरेलू फेस स् ब के बारे में जो त्वचा को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ब्लैकहेड्स हटाने में मदद करते हैं...

यह उपाय ब्लैकहेड्स हटाने में मदद करते हैं

नमक और नींबू- एक नींबू को आधा काटें, उस जगह पर नमक लगाएं और धीरे से चेहरे पर स्क्रब करें. स्क्रब लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा साफ हो. 5 मिनट तक अच्छी तरह स्क्रब करने के बाद, ठंडे पानी से चेहरा धो लें. हफ्ते में दो बार इस स्क्रब का इस्तेमाल करने से आपके चेहरे के काले धब्बे दूर हो जाएंगे.

चंदन और दूध- एक कटोरी में चंदन पाउडर और थोड़ा सा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे अपने चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर, अपने हाथों को पानी से गीला करके हल्के हाथों से चेहरे पर मलें और धो लें. चेहरा धोने के बाद, मॉइस्चराइजर लगाएं. हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करने से आपके रोमछिद्र सिकुड़ जाएंगे और ब्लैकहेड्स कम होंगे.

शहद और दालचीनी पाउडर- एक कटोरी में 2 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे ब्लैकहेड्स वाली जगह पर लगाकर 5 मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रब करें. फिर, साबुन या फेसवॉश का इस्तेमाल करके साफ़ पानी से चेहरा धो लें। हफ़्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करने से आपको अच्छा बदलाव दिखेगा.

ग्रीन टी- ग्रीन टी का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है. इसमें मौजूद उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट चेहरे से तेल और ब्लैकहेड्स हटाने में मदद करते हैं. इसके लिए, ग्रीन टी बनाने के बाद, पत्तियों या बैग को बिना फेंके, चेहरे पर धीरे से लगाएं और थोड़ी देर तक स्क्रब करें. फिर, गुनगुने पानी से चेहरा धोकर मॉइस्चराइजर लगाएं.

हल्दी और बेसन- एक कटोरी में 1 छोटा चम्मच बेसन, हल्दी और दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर धो लें. चेहरे के दाग-धब्बों से छुटकारा पाने और चेहरे पर चमक लाने के लिए इसे हफ़्ते में दो बार इस्तेमाल करें.

भाप- जो लोग नाक पर ब्लैकहेड्स की समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए हफ्ते में दो से तीन बार भाप लेनी चाहिए. ऐसा करने से स्किन के रोमछिद्र खुल जाएंगे. साथ ही स्किन से तेल का निकलना कम हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लैकहेड्स की समस्या कम होगी और स्किन मुलायम बनेगी.

बेकिंग सोडा और पानी- एक कटोरी में थोड़ा से पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. इस मिश्रण से ब्लैकहेड्स पर मसाज करें, 15 मिनट बाद अपने चेहरे को गर्म पानी से धो लें और मुलायम तौलिए से सुखा लें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा करने से ब्लैकहेड्स बनने वाली डेड स्किन सेल्स हट जाएंगी.

बदलते बस्तर की तस्वीर - तिरंगे के साथ नई सुबह

आज़ादी के 78 वर्ष बाद बस्तर के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों के 29 गांवों में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं था, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली वह घटना थी, जिसने दशकों से हिंसा, भय और लाल झंडे के साये में जी रहे इन इलाकों को नई पहचान दी। इन गांवों में तिरंगे का लहराना उस जज़्बे, त्याग और इच्छाशक्ति का प्रतीक है, जिसने असंभव लगने वाली चुनौती को संभव कर दिखाया।तिरंगा वहाँ फहरा जहाँ कभी नक्सलियों का राज था, जहाँ बंदूक की नली ही कानून थी और जहाँ ग्रामीण दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे। यह क्षण केवल बस्तर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक था।

बस्तर और नक्सलवाद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

बस्तर का नाम आते ही एक ओर इसकी प्राकृतिक सुंदरता, वनसम्पदा और आदिवासी संस्कृति याद आती है, वहीं दूसरी ओर नक्सलवाद और हिंसा की लंबी छाया भी जुड़ जाती है।

नक्सल आंदोलन की जड़ें 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से पड़ी थीं, लेकिन 1980 और 90 के दशक में यह छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर क्षेत्र में गहराई तक फैल गया। घने जंगल, कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ और प्रशासन की कमजोर पहुँच ने नक्सलियों को पनपने का अवसर दिया। आदिवासियों की समस्याओं, शोषण और उपेक्षा को मुद्दा बनाकर उन्होंने अपनी पकड़ मज़बूत की।

बस्तर के हजारों गांव लंबे समय तक लाल गलियारे का हिस्सा रहे। यहाँ सरकार का अधिकार कागज़ों में ही था, ज़मीन पर लाल झंडे और नक्सली संगठन ही कानून की तरह काम करते थे। स्कूल जलाए जाते थे, सड़क बनाने वालों पर हमले होते थे और पुलिस व सुरक्षा बल लगातार नक्सल हिंसा का सामना करते रहे।

भय से विश्वास तक की यात्रा

इन इलाकों में दशकों तक डर ही जीवन का हिस्सा रहा। ग्रामीण दिन ढलते ही घरों से बाहर निकलने से डरते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएँ लगभग नदारद थीं। गाँव से बाहर निकलना, नौकरी या व्यापार करना तो दूर की बात थी, लोग रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए भी नक्सलियों की अनुमति पर निर्भर रहते थे। लेकिन हाल के वर्षों में परिदृश्य बदलना शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने गाँव-गाँव पहुँच बनानी शुरू की। सरकार ने यह समझा कि केवल बंदूक से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसके लिए दिल जीतना ज़रूरी है। ग्रामीणों में धीरे-धीरे यह भरोसा पैदा हुआ कि राज्य उनका दुश्मन नहीं, बल्कि साथी है।

आज उन्हीं गांवों में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, महिलाएँ आत्म-सहायता समूहों से जुड़कर रोज़गार पा रही हैं और युवा रोजगार की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात—आज वे बिना डरे तिरंगे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गा पा रहे हैं।

सुरक्षा बलों की भूमिका

इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे सुरक्षा बलों का त्याग और साहस है।

- हाल के वर्षों में नई रणनीति अपनाई गई—छोटे-छोटे कैम्प, निरंतर गश्त और ग्रामीणों से संवाद।
- आत्मसमर्पण नीति के तहत हजारों नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की।
- लगातार दबाव ने नक्सली संगठन की कमर तोड़ी और उनकी गतिविधियाँ सीमित हो गईं।

बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जैसे जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने जान की बाज़ी लगाकर गाँव-गाँव तक पहुँच बनाई। सैकड़ों जवान शहीद भी हुए, लेकिन उनके बलिदान ने आज बस्तर को नई सुबह दी है।

सरकार का दृष्टिकोण और योजनाएँ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर को सरकार के संकल्प का परिणाम बताया। उनके अनुसार,

बस्तर अब भय और हिंसा से बाहर निकलकर प्रगति, समृद्धि और विश्वास की ओर बढ़ रहा है। हमारा वचन है कि हर गांव तक विकास की रोशनी पहुँचेगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा—आज जिन गांवों में तिरंगा फहराया गया, वहाँ दशकों तक लाल झंडे का खौफ छाया रहा। यह बस्तर में नई सुबह का प्रतीक है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल सुरक्षा उपायों से नहीं, बल्कि विकास से ही स्थायी समाधान निकलेगा।

- प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुँच रहा है।
- नियद नेल्ला नार योजना के तहत सड़क, बिजली और शिक्षा की सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।
- स्वास्थ्य शिविर और स्कूलों ने ग्रामीणों का विश्वास मजबूत किया है।

सामाजिक और सांस्कृतिक असर

इन बदलावों का असर केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी दिखाई देता है।

- शिक्षा का प्रसार होने से नई पीढ़ी हिंसा से दूर रहकर रोजगार और करियर की ओर बढ़ रही है।
- महिलाएँ आत्म-सहायता समूहों के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।
- स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचने से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
- सांस्कृतिक आयोजनों में अब राष्ट्रगान और तिरंगे के साथ स्थानीय परंपराओं का मेल हो रहा है।

राजनीतिक महत्व

यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक सफलता नहीं है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से यह संभव हो पाया है। बस्तर में तिरंगे का फहरना उस विचार को मज़बूत करता है कि भारत की एकता और अखंडता केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने से कायम रहती है। यह घटना सरकार की सुशासन और विकास नीति का जीता-जागता उदाहरण है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सकारात्मक संदेश देती है।

भविष्य की राह

हालांकि तिरंगे का फहराना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन

चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

- अभी भी कुछ इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी बनी हुई है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की सुविधाओं को और मज़बूत करने की ज़रूरत है।
- सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ग्रामीणों में पैदा हुआ विश्वास लगातार बना रहे।

भविष्य की राह यही है कि सुरक्षा और विकास दोनों का संतुलित मेल कायम रखा जाए। जब तक ग्रामीणों को लगेगा कि सरकार उनके साथ है और उनके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना रही है, तब तक हिंसा की कोई भी ताक़त उन्हें नहीं डिगा पाएगी। बस्तर के इन 29 गांवों में फहराता तिरंगा केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और बदलाव का प्रतीक है। यह संदेश है कि जब इच्छाशक्ति, रणनीति और जनभागीदारी मिलकर काम करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है।

यह घटना इतिहास के उस पन्ने पर दर्ज हो चुकी है, जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाएगा कि हिंसा की अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंततः सुबह होती है।

कर्रेगुट्टा से लेकर नुलकातोंग तक लहराता तिरंगा आज बस्तर के उज्ज्वल भविष्य की गवाही दे रहा है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा...

21 जुलाई 2025 की शाम भारतीय राजनीति में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। 74 वर्षीय धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण और डॉक्टर की सलाह को बताया, लेकिन इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में अनेक सवाल भी खड़े कर दिए हैं।

धनखड़ का कार्यकाल और योगदान

जगदीप धनखड़ ने 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वे राज्यसभा के पदेन सभापति भी रहे और अपने कार्यकाल के दौरान कई बार चर्चा में रहे। उन्होंने विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संतुलन की बात बार-बार दोहराई और कई बार उच्च सदन की गरिमा को बनाए रखने की कोशिशों के लिए सराहना भी पाई।

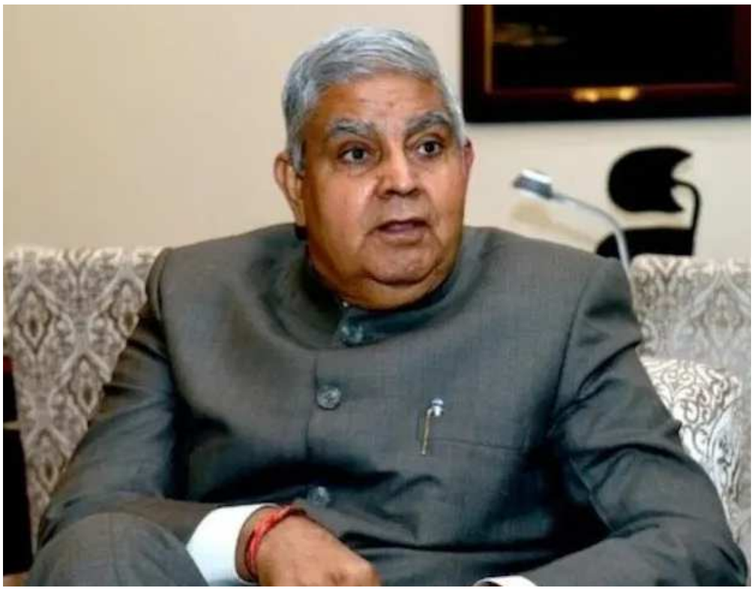

उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक होना था, लेकिन संसद के मानसून सत्र के बीच में दिया गया यह इस्तीफा न केवल अनपेक्षित रहा बल्कि ऐतिहासिक भी बन गया क्योंकि सत्र के दौरान इस्तीफा देने वाले वे पहले उपराष्ट्रपति बने।

इस्तीफे की वजह - सिर्फ स्वास्थ्य..?

धनखड़ ने अपने इस्तीफे पत्र में लिखा-

सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं...

उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सांसदों के सहयोग का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे भारत की प्रगति और भविष्य को लेकर आशान्वित हैं।

लेकिन इस पत्र के बावजूद, राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी नेताओं को यह फैसला अचानक और अस्पष्ट प्रतीत हुआ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा-

ये इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी है... इससे कहीं अधिक है जो दिखाई दे रहा है।

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसे व्यक्तिगत क्षति बताया और कहा कि वे धनखड़ की गैरमौजूदगी महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य संबंधित घटनाएं - पृष्ठभूमि

हालांकि धनखड़ के इस्तीफे की घोषणा के साथ ही स्वास्थ्य कारणों की बात की गई, लेकिन इससे जुड़े कुछ पिछले घटनाक्रम इस बात को कुछ हद तक पुष्ट करते हैं-

- 25 जून 2025 को उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के बाद उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई थी और उन्हें तत्काल उपचार दिया गया था।
- 9 मार्च 2025 को उन्हें AIIMS दिल्ली में भी सीने में दर्द के चलते भर्ती किया गया था।

इन घटनाओं के आधार पर उनके इस्तीफे को पूर्णतः निराधार नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह यह ऐन सत्र के बीच हुआ, उसने कयासों को जन्म दिया।

विवाद और सार्वजनिक घटनाएं

धनखड़ का कार्यकाल पूरी तरह विवादों से रहित नहीं रहा। एक उल्लेखनीय घटना 19 दिसंबर 2023 की है, जब TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर उनकी मिमिक्री की थी और राहुल गांधी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस प्रकरण ने उस समय भारी विवाद खड़ा कर दिया था और उपसभापति के पद की गरिमा पर प्रश्न उठे थे।

हालांकि उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती खाई को लेकर वे अक्सर चिंतित नजर आते थे।

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा निस्संदेह भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ रहा । स्वास्थ्य कारणों को आगे रखकर लिए गए इस फैसले के पीछे की सच्चाई जो भी हो, उनका योगदान और संवैधानिक पद पर संतुलन बनाए रखने की उनकी कोशिशें स्मरणीय रहेंगी।

उनका कार्यकाल हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र में संविधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति की भूमिका केवल औपचारिक नहीं, बल्कि अत्यंत प्रभावशाली होती है, विशेषकर जब राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर हो।

महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति की नई राह- छत्तीसगढ़ में 'रेडी-टू-ईट' पहल...

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए महिला स्व-सहायता समूहों को एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। सरकार ने पूरक पोषण आहार 'रेडी-टू-ईट' (Ready-to-Eat) निर्माण और वितरण की जिम्मेदारी पुनः महिला समूहों को सौंपी है। यह पहल केवल एक योजना नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और कुपोषण उन्मूलन की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।

रायगढ़ से हुई शुरुआत

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कोतरलिया में रेडी-टू-ईट निर्माण इकाई का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं मशीन चलाकर उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण किया और महिलाओं को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

रायगढ़ जिले में कुल 2709 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन सभी केंद्रों के लिए 10 महिला स्व-सहायता समूहों का चयन किया गया है। फिलहाल कोतरलिया इकाई से उत्पादन प्रारंभ हो चुका है और जल्द ही जिले के अन्य ब्लॉकों—रायगढ़ शहरी, रायगढ़ ग्रामीण, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, मुकड़ेगा, धरमजयगढ़ एवं कापू—में भी इकाइयाँ शुरू होंगी।

महिला समूहों को प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज (PMFME) योजना के तहत पूंजीगत सब्सिडी भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे आधुनिक मशीनरी और संसाधनों का उपयोग कर सकें।

पायलट प्रोजेक्ट के छह जिले

सरकार ने इस परियोजना को प्रथम चरण में पायलट रूप से छह जिलों में लागू किया है-

बस्तर,दंतेवाड़ा,बलौदाबाजार,कोरबा,रायगढ़,सूरजपुर

इन जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट उत्पादन और आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

क्यों खास है यह पहल?

1. महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर

यह योजना महिला स्व-सहायता समूहों को एक स्थायी व्यवसाय उपलब्ध कराती है। अब ये समूह केवल बचत और ऋण तक सीमित न रहकर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्यमी बनेंगे।

- समूहों को उत्पादन और वितरण से नियमित आय होगी।
- रोजगार के स्थानीय अवसर बढ़ेंगे।

- लखपति दीदी अभियान से छत्तीसगढ़ की महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ेंगी।

2. कुपोषण पर प्रहार

छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में कुपोषण अब भी एक गंभीर समस्या है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार वितरण की पारंपरिक व्यवस्था कई बार विवादों में रही है।

- स्थानीय स्तर पर उत्पादन से ताजगी और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
- बच्चों और गर्भवती/धात्री माताओं को संतुलित व पौष्टिक आहार मिलेगा।
- कुपोषण दर में गिरावट लाने की दिशा में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है।

3. सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता

जब महिलाएं अपने गाँव या जिले में उत्पादन इकाइयाँ संचालित करेंगी तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

- महिलाएं अब नौकरी मांगने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बनेंगी।
- यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगी और गांव स्तर पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की दृष्टि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा कि यह परियोजना महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता देने के साथ-साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार उपलब्ध कराने की दोहरी जिम्मेदारी निभाएगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ देशभर में प्रधानमंत्री मोदी के 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ से हुई शुरुआत को पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा, यह मॉडल शीघ्र ही सभी जिलों में लागू होगा और छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा।

चुनौतियाँ भी कम नहीं

हालांकि योजना उत्साहजनक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं-

- गुणवत्ता नियंत्रण- उत्पादन के हर चरण में मानक बनाए रखना आवश्यक होगा।
- प्रशिक्षण और प्रबंधन- ग्रामीण महिलाएं मशीनरी और उत्पादन प्रक्रिया की विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए निरंतर प्रशिक्षण और निगरानी की जरूरत होगी।
- आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain)- समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों तक आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी।
- भ्रष्टाचार और अनियमितता की रोकथाम- पारदर्शिता और निगरानी तंत्र मजबूत करना होगा।

यदि सरकार और प्रशासन इन चुनौतियों पर ध्यान देता है तो यह परियोजना लंबे समय तक टिकाऊ और प्रभावी साबित हो सकती है।

भविष्य की राह

पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राज्य सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू करेगी।

- सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला समूहों के माध्यम से ही ऋ्ञश्व आहार का उत्पादन और वितरण होगा।
- SHG इकाइयों को तकनीकी प्रशिक्षण, मशीनरी, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए विशेष सहयोग मिलेगा।
- आगे चलकर यह महिला समूह स्थानीय बाजार में भी अपने उत्पाद बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय कई गुना बढ़ सकती है।

रायगढ़ से प्रारंभ हुई यह योजना केवल एक पोषण कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास का मजबूत मॉडल है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी, बच्चों और माताओं को पौष्टिक आहार मिलेगा और राज्य में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को नया बल मिलेगा।

यदि यह पहल सफल होती है, तो छत्तीसगढ़ न केवल अपने लक्ष्य लखपति दीदी की ओर तेजी से बढ़ेगा, बल्कि देशभर में महिला उद्यमिता और पोषण सुरक्षा का प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा।

ESIC है कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा कवच

कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या है?

कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) भारत सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत प्रदान की जाने वाली एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) एक सरकारी संगठन है जो इस योजना का प्रबंधन करता है। यह कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता तब प्रदान की जाती है जब कोई कर्मचारी बीमारी, कार्यस्थल पर चोट लगने या प्रसूति के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। ESIS एक स्व-वित्तपोषित योजना है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी अपने वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार इस योजना में नियमित मासिक अंशदान करते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) एक स्व-वित्तपोषित योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत नियमित मासिक अंशदान के रूप में इस योजना में जमा करते हैं। यह योजना कर्मचारियों को किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण पड़ने वाले वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

भारतीय संसद ने 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत लगभग 1.20 लाख कर्मचारी आते हैं। यह अधिनियम योजना की वैधता से संबंधित कई नियम और शर्तें निर्दिष्ट करता है, जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की ज़िम्मेदारियाँ और बीमित कर्मचारियों की पात्रता और कर्तव्य शामिल हैं।

ऐसी आकस्मिकताओं में उत्पन्न होने वाले शारीरिक या वित्तीय संकट को संतुलित करने या उसे नकारने के लिए अधिनियम में किए गए सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का उद्देश्य संकट के दौरान अभाव, अभाव और सामाजिक पतन से सुरक्षा के माध्यम से मानव गरिमा को बनाए रखना है, साथ ही समाज को सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्यबल को बनाए रखने और जारी रखने में सक्षम बनाना है।

ईएसआईएस (कर्मचारी राज्य बीमा योजना) की मुख्य विशेषताएं

यदि आप इस सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा योजना की बारीकियों को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो यहां इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और लाभ दिए गए हैं-

- ईएसआईएस 26 हफ्तों के लिए मातृत्व कवर प्रदान करता है। इसके अलावा, अगर वेतन 70 दिनों के अंशदान के अधीन है, तो कवर को एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
- दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के दौरान लाभार्थियों को किश्तों में भुगतान की पेशकश की जाती है।
- यह बेरोज़गार सदस्य को तीन साल का कवरेज प्रदान करता है। हालाँकि, यह तभी संभव है जब सदस्य स्थायी विकलांगता और पिछली कार्यस्थल जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करे।
- जब कोई व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो यह कर्मचारी के वेतन का 90त्न प्रदान करता है।
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कर्मचारी को उसकी अक्षमता और स्वास्थ्य की बहाली के समय पूर्ण चिकित्सा देखभाल और ध्यान प्रदान किया जाता है।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उद्देश्य 21,000 रुपये या उससे कम मासिक भुगतान वाले सभी श्रमिकों को कवरेज प्रदान करना है।

- बीमाकर्ता और उनके आश्रित सदस्य विशिष्ट बीमारियों के विरुद्ध स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- नियोक्ताओं के लिए वर्तमान अंशदान दर 3.25% है, और कर्मचारियों के लिए यह देय वेतन का 0.75% है। सरकार ने 2019 में कुल अंशदान को 6.5% से घटाकर 4% कर दिया। ध्यान दें कि 137 रुपये से कम दैनिक वेतन वाले श्रमिकों को अपना हिस्सा देने से छूट दी गई है।

ईएसआईएस के लाभ

ईएसआईसी वेबसाइट के अनुसार, ईएसआई योजना से ये लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं-

बीमारी लाभ (एसबी)

बीमारी लाभ, प्रमाणित बीमारी के दौरान बीमित कर्मचारियों को प्रति वर्ष अधिकतम 91 दिनों के लिए देय वेतन का 70% नकद मुआवज़ा है। बीमारी लाभ के लिए पात्र होने के लिए, बीमित व्यक्ति को 6 महीने की अंशदान अवधि में 78 दिनों के लिए अंशदान करना होगा।

चिकित्सा लाभ

बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को बीमा योग्य रोज़गार शुरू होने के दिन से ही पूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है। बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य के इलाज पर होने वाले खर्च की कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा, 120 रुपये के सांकेतिक वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर , स्थायी रूप से विकलांग या सेवानिवृत्त बीमित व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है।

मातृत्व लाभ (एमबी)

प्रसव या गर्भावस्था के लिए मातृत्व लाभ 26 सप्ताह के लिए देय है, जिसे पूर्ण मजदूरी दर पर चिकित्सा सलाह पर एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, जो पूर्ववर्ती दो अंशदान अवधियों में 70 दिनों के लिए अंशदान के अधीन है।

बेरोजगारी भत्ता

कोई बीमित व्यक्ति जो बीमाकृत होने के दो या अधिक वर्षों के बाद कारखाना/प्रतिष्ठान बंद होने, छंटनी या गैर-रोजगार चोट के कारण 40% से कम स्थायी अशक्तता के कारण बेरोजगार हो जाता है, वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार है, अर्थात जीवनकाल के दौरान अधिकतम दो वर्षों तक मजदूरी का 50%।

मृत्यु लाभ

यदि किसी बीमित कर्मचारी की व्यावसायिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित परिवार के सदस्य मृतक के वेतन के 90% के बराबर मासिक मुआवज़ा प्राप्त कर सकते हैं। आश्रित माता-पिता और जीवनसाथी मृत्यु तक इन लाभों का आनंद ले सकते हैं, जबकि आश्रित बच्चे 25 वर्ष की आयु से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के समावेशन और बहिष्करण

ईएसआईएस भारत के अधिकांश नियोजित निवासियों को कवर करता है। हालाँकि, इस योजना में नामांकन करने से पहले, आपको इसके समावेशन और बहिष्करणों पर एक नज़र डालनी चाहिए-

समावेशन

- यह योजना अब रेस्तरां, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, सिनेमाघरों और प्रीव्यू थिएटरों, होटलों, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रमों और दुकानों तक विस्तारित हो गई है।
- यह योजना दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले निजी शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों पर भी लागू होती है। हालाँकि, ध्यान रखें कि यह केवल कुछ चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर ही लागू होती है।

बहिष्कार

- ईएसआईसी योजना वर्तमान में 21,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों को कवर नहीं करती है। हालाँकि,

विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम वेतन सीमा 25,000 रुपये प्रति माह है।

- महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में कवरेज के लिए वर्तमान सीमा अभी भी बीस कर्मचारी है, जबकि अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में यह सीमा दस कर्मचारी नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के लिए पात्रता मानदंड

1 जनवरी 2017 से, कर्मचारियों के लिए कवरेज की मासिक वेतन सीमा 21,000 रुपये प्रति माह है। पात्र कर्मचारियों को ईएसआईसी कार्यक्रम में नामांकित करना नियोक्ता का दायित्व है। अंशदान कर्मचारियों की कमाई क्षमता के आधार पर उनके वेतन के एक निश्चित अनुपात में दिया जाता है, फिर भी उन्हें बिना किसी भेदभाव के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाते हैं।

ईएसआईसी के लिए पंजीकरण कैसे करें?

नियोक्ताओं द्वारा ईएसआई पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और पंजीकरण प्रक्रिया में भौतिक आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ईएसआईसी के साथ अपने संगठन या प्रतिष्ठान को पंजीकृत करने के चरण नीचे दिए गए हैं=

- आधिकारिक ईएसआईसी पोर्टल से फॉर्म नंबर 1 (नियोक्ता पंजीकरण फॉर्म) पीडीएफ में डाउनलोड करें और आवश्यक विवरण भरें।
- आपको अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी पर एक पुष्टिकरण मेल प्राप्त होगा जिसमें उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का विवरण होगा।
- अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके ईएसआईसी पोर्टल पर लॉग इन करें और %नया नियोक्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन मेनू से, %इकाई का प्रकार चुनें, फिर उसे सबमिट करें।
- सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ नियोक्ता पंजीकरण फॉर्म संख्या 1 भरें।
- अग्रिम अंशदान का भुगतान शीर्षक वाले पृष्ठ पर पुनः निर्देशित होने के बाद, छह महीने के अग्रिम अंशदान के लिए राशि दर्ज करें और पसंदीदा भुगतान मोड चुनें।
- भुगतान पूरा होने के बाद, आपको एक पंजीकरण पत्र (सी-11) दिया जाएगा जिसमें 17 अंकों का ईएसआईसी पंजीकरण नंबर होगा।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

ईएसआईसी के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास रखें=

- दुकान एवं स्थापना अधिनियम या कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र या लाइसेंस।
- निजी लिमिटेड कंपनियों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र और साझेदारी फर्मों के लिए साझेदारी विलेख।
- कंपनी का एसोसिएशन का ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख।
- सभी श्रमिकों की सूची तथा उनके मासिक पारिश्रमिक का विवरण।
- सभी कर्मचारियों और व्यावसायिक इकाई का पता प्रमाण और पैन कार्ड।

सफल नामांकन के बाद, प्रत्येक श्रमिक को एक ईएसआई कार्ड या पहचान कार्ड प्राप्त होता है, जिसे उन्हें हर बार चिकित्सा उपचार के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिखाना होगा7

कर्मचारी राज्य बीमा कार्ड (पहचान कार्ड)

ईएसआई कार्ड या पहचान कार्ड, ईएसआई योजना के तहत नामांकित बीमित व्यक्ति को दिया जाने वाला एक स्वास्थ्य कार्ड है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी ईएसआई कार्ड या ई-पहचान कार्ड दिखाकर ईएसआई नेटवर्क के अस्पतालों या औषधालयों में बीमारी और चिकित्सा लाभों का दावा कर सकते हैं। ईएसआई योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ बीमित व्यक्ति या लाभार्थियों और उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय के लिए कवरेज के रूप में हैं।

ईएसआई कार्ड (पहचान कार्ड) के लिए आवेदन कैसे करें?

जब कोई श्रमिक ईएसआई योजना के अंतर्गत नामांकित होता है तो ईएसआईसी से ईएसआई कार्ड (पहचान कार्ड) प्राप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-

इस कार्ड में लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, पता और एक विशिष्ट ईएसआई बीमा संख्या जैसी जानकारी शामिल होती है। इसमें बीमित व्यक्ति की तस्वीर और उसके आश्रितों की जानकारी भी शामिल होती है।

ईएसआई कार्ड (पहचान कार्ड) डाउनलोड करने के लिए, नियोक्ता को ईएसआईसी पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करना होगा और संबंधित कर्मचारी का विवरण भरना होगा। पूरा होने पर, ईएसआईसी कर्मचारी के पते पर एक चुंबकीय स्मार्ट कार्ड जारी करेगा, या उन्हें इसे लेने के लिए ईएसआईसी शाखा जाना पड़ सकता है।

ईएसआई लाभ का दावा कैसे करें?

ईएसआईएस के लाभार्थी के रूप में, कोई भी व्यक्ति दो प्रकार के लाभों का दावा कर सकता है-

चिकित्सा लाभ

बीमित व्यक्ति और उनके आश्रित चिकित्सा सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी ईएसआई पैनलबद्ध अस्पताल में जाना होगा।

नकद लाभ

ईएसआई योजना के लाभार्थी कर्मचारी विकलांगता, बीमारी,

मातृत्व, आश्रित, अंतिम संस्कार लागत, बेरोजगारी और व्यावसायिक एवं शारीरिक पुनर्वास के मामले में नकद लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ईएसआईएस के क्या करें और क्या न करें

ईएसआईएस के लाभार्थी के रूप में, आपको निम्नलिखित आवश्यक बातों की जानकारी होनी चाहिए-

- एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाते समय, सुनिश्चित करें कि आपके नए नियोक्ता को आपके ईएसआई पंजीकरण संख्या के बारे में जानकारी हो। इस तरह, आप इसके लाभों का लाभ उठाते रहेंगे।
- सुनिश्चित करें कि आप पहचान कार्ड को नुकसान न पहुंचाएं या खो न दें, क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य पूरा करता है।
- यदि कार्ड खो जाए तो आपको या आपके किसी आश्रित को तुरन्त निकटतम शाखा कार्यालय या डिस्पेंसरी में इसकी सूचना देनी होगी।
- ईएसआई अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ईएसआई कार्ड/पहचान कार्ड या ई-पहचान कार्ड आवश्यक है।
- डॉक्टर के निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

महतारी वंदन योजना से रक्षाबंधन की खुशियाँ हुईं दुगनी...

छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना ने प्रदेश की लाखों महिलाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस योजना से मिली आर्थिक सहायता से महिलाएं न केवल अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार भी पूरे उल्लास और आत्मसम्मान के साथ मना रही हैं।

बालोद जिले के ग्राम अरौद की लाभार्थी टोमिन बाई सेवता ने बताया कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि से वह अपने भाई के लिए राखी और मिठाई खरीदी हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना उनके लिए किसी उपहार से कम नहीं है। वहीं यामिनी कोठारी ने योजना की 18वीं किस्त मिलने पर बताया कि इस बार रक्षाबंधन खास होगा, क्योंकि अब वह अपने खर्च खुद उठा पा रही हैं।

नारायणपुर जिले की श्रीमती हीरोंदी कड़ियाम, जो पहले साप्ताहिक बाजारों में लाई और चना बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करती थीं, अब महतारी वंदन योजना से मिली राशि को अपने व्यवसाय में लगाकर मूंगफली, नमकीन, बिस्किट, नड्डा जैसी खाद्य पदार्थ भी बेच रही हैं। उनकी आय पहले से दोगुनी हो गई है। हीरोंदी का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर अपने बच्चों और परिवार के लिए मिठाइयाँ और उपहार लेने में उन्हें कोई हिचक नहीं है।

महासमुंद की पुष्पा प्रजापति ने बताया कि पहले उन्हें हर छोटी- छोटी जरूरत के लिए पति या बेटे से पैसे मांगने पड़ते थे, लेकिन अब इस योजना की राशि से वे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी निकाल रही हैं और रक्षाबंधन के लिए श्रृंगार सामग्री व उपहार भी खरीद रही हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता ला रही है और स्वरोजगार से आगे बढ़ रही है।

इन सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को धन्यवाद देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और खुशियों का उत्सव है, जिनकी वजह से उनके जैसे हजारों महिलाओं का जीवन बदल रहा है।

अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ और रूस से तेल खरीद पर जुर्माना भारत-अमेरिका संबंधों में नई दरार...

अगस्त 2025 में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार जगत में एक बड़ा झटका देखने को मिला, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यह नया टैरिफ पहले से लागू 25 प्रतिशत शुल्क के ऊपर लगाया गया, जिससे कुल शुल्क दर 50 प्रतिशत हो गई। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना बताया गया, जिसे अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक हितों के विपरीत माना। साथ ही, अमेरिका ने भारत के कुछ सरकारी और निजी संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया, यह आरोप लगाते हुए कि वे रूस के ऊर्जा निर्यात से जुड़े लेन-देन में शामिल हैं। इस कदम ने न केवल व्यापार जगत को हिला दिया, बल्कि भारत- अमेरिका संबंधों में भी एक नई खटास ला दी।

अमेरिका के टैरिफ लगाने का कारण

अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि रूस- यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को आर्थिक लाभ पहुँचाने वाली किसी भी गतिविधि पर कड़ा कदम उठाना आवश्यक है। भारत ने पिछले दो वर्षों में रूस से रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, जिससे भारत की ऊर्जा लागत तो घटी, लेकिन अमेरिका को यह कदम रूस को अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता जैसा लगा।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने आदेश में कहा कि भारत जैसे मित्र देशों से उम्मीद है कि वे अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर दबाव बढ़ाएँ, लेकिन भारत का रूसी तेल खरीदना हमारे सामरिक हितों के विपरीत है।

टैरिफ का स्वरूप और प्रभावी तिथि

- मौजूदा शुल्क- पहले से 25प्रतिशत आयात शुल्क लागू था।
- नया शुल्क- अतिरिक्त 25प्रतिशत जोड़ा गया, कुल 50प्रतिशत।
- प्रभावी तिथि- 27 अगस्त 2025 से।

इसका सीधा असर भारतीय निर्यात पर पड़ेगा, खासकर उन उद्योगों पर जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं—जैसे टेक्सटाइल, रत्न-आभूषण, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत सरकार ने इस कदम को अनुचित और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की भावना के खिलाफ बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों से तेल खरीदने का अधिकार रखता है और यह किसी तीसरे देश की नीतियों के दबाव में नहीं होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ

बातचीत के बाद कहा—भारत अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेगा। हम रूस के साथ अपने संबंध और गहरे करेंगे। इस बयान से साफ है कि भारत अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद करने के मूड में नहीं है।

आर्थिक असर

GDP पर संभावित असर-

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात को बड़ा झटका लगेगा, जिससे त्ष्ठक्कविकास दर में लगभग 1त्न की गिरावट आ सकती है।

उद्योग पर असर

- टेक्सटाइल और गारमेंट- अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वस्त्र खरीदार है। 50त्न शुल्क लगने से ऑर्डर घटेंगे, जिससे पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात के उद्योग प्रभावित होंगे।
- रत्न-आभूषण- सूरत का हीरा उद्योग अमेरिका पर भारी निर्भर है। टैरिफ के बाद प्रतिस्पर्धा कमज़ोर होगी और ऑर्डर अन्य देशों (थाईलैंड, वियतनाम) को जा सकते हैं।
- ऑटो पार्ट्स- पुणे और गुरुग्राम के निर्यातक अमेरिकी बाजार में महंगे पड़ेंगे, जिससे बिक्री घट सकती है।

रुपये और शेयर बाजार पर असर्

घोषणा के बाद रुपये में गिरावट आई और निवेशकों ने 'सेफ-हेवन' संपत्तियों जैसे सोना-चांदी में निवेश बढ़ा दिया। शेयर बाजार में भी निर्यात-आधारित कंपनियों के शेयर गिरे।

रणनीतिक असर

(क) रक्षा साझेदारी में ठंडापन

अमेरिकी मीडिया में यह रिपोर्ट आई कि भारत कुछ अमेरिकी हथियार सौदों को रोक सकता है, हालांकि भारत सरकार ने इसे अफवाह बताया। फिर भी, यह स्थिति रक्षा सहयोग पर नकारात्मक असर डाल सकती है।

(ख) भू-राजनीतिक समीकरण

अमेरिका- भारत रणनीतिक साझेदारी, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में, पिछले वर्षों में मजबूत हुई थी। लेकिन यह टकराव चीन और रूस के लिए एक अवसर हो सकता है कि वे भारत को और करीब लाएँ।

क्या संबंध बिगड़ गए हैं?

कूटनीतिक भाषा में कहा जाए तो संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

- पहले- दोनों देश व्यापार, रक्षा और तकनीकी साझेदारी में प्रगति कर रहे थे।
- अब- रूस मुद्दे पर मतभेद सामने हैं, और अमेरिका का टैरिफ भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि वह आर्थिक दबाव भी इस्तेमाल करेगा।

हालाँकि, यह भी सच है कि भारत और अमेरिका दोनों के पास एक-दूसरे की आवश्यकता बनी हुई है—अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत का समर्थन चाहिए, और भारत को उच्च तकनीक, निवेश और रक्षा सहयोग में अमेरिका की ज़रूरत है।

भारत के पास विकल्प क्या हैं?

बाजार विविधीकरण- अमेरिकी निर्भरता घटाकर यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ASEAN देशों में निर्यात बढ़ाना।

घरेलू उद्योग सुदृढ़ीकरण- उत्पादन लागत घटाकर और तकनीक सुधारकर उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।

द्विपक्षीय वार्ता- अमेरिका के साथ उच्च-स्तरीय कूटनीतिक संवाद कर के टैरिफ कम करने या छूट दिलाने की कोशिश।

ऊर्जा आयात में संतुलन- रूस से तेल खरीद जारी रखते हुए, अमेरिका और मध्य-पूर्व से भी आयात बढ़ाकर दबाव कम करना।

अमेरिका का यह कदम केवल एक आर्थिक प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है—कि वैश्विक राजनीति में आर्थिक दबाव एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के लिए यह एक चेतावनी है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक विविधता, घरेलू सुदृढ़ीकरण और कूटनीतिक संतुलन बेहद जरूरी है।

अगर भारत इस संकट को अवसर में बदलने में सफल होता है, तो वह न केवल अमेरिकी दबाव को झेल पाएगा, बल्कि नए वैश्विक बाजारों में अपनी पकड़ भी मजबूत कर सकेगा। लेकिन अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसका दीर्घकालिक असर भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों पर पड़ेगा।

भविष्य के संभावित नुकसान

क्षेत्र	संभावित नुकसान
निर्यात	अमेरिकी बाजार में 50 प्रतिशत टैरिफ के कारण प्रतिस्पर्धा कम, ऑर्डर घटेंगे
GDP	0.8प्रतिशत-1प्रतिशत तक गिरावट संभव
रोजगार	टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी और मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियों पर खतरा
विदेश नीति	अमेरिका से दूरी और रूस-चीन के साथ बढ़ती निकटता, जिससे पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते प्रभावित
निवेश	अमेरिकी कंपनियों के निवेश निर्णयों में देरी

कुम्हारी टोल प्लाजा 2026 जून में होगा बंद- केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति....

छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से उठ रही मांग और निरंतर प्रयासों के बाद कुम्हारी टोल प्लाजा को जून 2026 में बंद करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल इस मामले में लगातार सक्रिय रहे और उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि यह निर्णय लिया गया।

भारतमाला परियोजना का हिस्सा है नई सड़क

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत आरंग-दुर्ग-रायपुर बाईपास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

- कुल लंबाई- 92 किलोमीटर
- उद्देश्य- शहर के बीच से गुजरने वाले भारी वाहनों और लंबी दूरी के यातायात को शहर से बाहर डायवर्ट करना
- निर्माण समयसीमा- जून 2026 तक पूर्ण होने का लक्ष्य.

इस बाईपास के बन जाने से रायपुर, भिलाई और दुर्ग के बीच यातायात सुगम होगा और शहरों के भीतर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम होगा।

क्यों बंद होगा कुम्हारी टोल प्लाजा

कुम्हारी टोल प्लाजा रायपुर और भिलाई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जहाँ से रोज़ाना हजारों वाहन गुजरते हैं। यह टोल प्लाजा कई वर्षों से संचालित हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों और रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए यह आर्थिक और समय की दृष्टि से असुविधा का कारण बनता रहा है।

जैसे ही नया बाईपास तैयार होगा,

- भारी वाहनों का रूट कुम्हारी से हटकर नए बाईपास पर शिफ्ट हो जाएगा।
- पुराने मार्ग पर टोल की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- इसी कारण जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

स्थानीय जनता को मिलने वाले लाभ

1. आर्थिक बचत - रोज़ाना टोल शुल्क चुकाने वाले हजारों वाहन मालिकों को राहत।
2. समय की बचत - टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों से मुक्ति।
3. ट्रैफिक में कमी- भारी वाहनों के हटने से स्थानीय मार्ग पर जाम की समस्या घटेगी।
4. प्रदूषण में कमी - धीमी गति और ट्रैफिक जाम के कारण होने वाला वायु प्रदूषण कम होगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की भूमिका

इस फैसले के पीछे रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल की लगातार पैरवी और प्रयास अहम रहे। उन्होंने संसद से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रालयों तक इस मुद्दे को उठाया, जिससे अंततः केंद्र ने स्वीकृति प्रदान की। उनका मानना है कि यह निर्णय न केवल रायपुर और भिलाई के बीच यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति देगा।

भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला यह बाईपास न केवल टोल मुक्त सफर का रास्ता खोलेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों तक तेज़ और सुगम कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। इससे माल ढुलाई सस्ती होगी और निवेशकों के लिए क्षेत्र और भी आकर्षक बन जाएगा।

जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा का बंद होना छत्तीसगढ़ के यात्रियों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगा। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला आरंगङ्कदुर्गङ्करायपुर बाईपास प्रदेश की सड़क संरचना को एक नया रूप देगा और आने वाले वर्षों में क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति को तेज़ करेगा।

कृष्ण जन्माष्टमी- भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का पावन उत्सव

कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे गोकुलाष्टमी या जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख एवं पावन पर्वों में से एक है। यह त्योहार भगवान विष्णु के आठवें अवतार, श्रीकृष्ण के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, अर्धरात्रि के समय भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। यह तिथि सामान्यतः अगस्त अथवा सितंबर माह में पड़ती है। श्रीकृष्ण का जन्म केवल एक देवावतार की घटना नहीं मानी जाती, बल्कि यह मानव समाज में धर्म, प्रेम, न्याय और करुणा के पुनर्स्थापन का प्रतीक भी है। यही कारण है कि भारत ही नहीं, बल्कि विश्वभर में जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और उत्साह से मनाया जाता है।

श्रीकृष्ण का जन्म और बाल्यकाल

भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी के कारागार में हुआ। उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव थे। देवकी का भाई कंस एक अत्याचारी राजा था, जिसने अपनी बहन के आठवें पुत्र से मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर, देवकी और वसुदेव को कैद में डाल दिया। जैसे ही श्रीकृष्ण का जन्म हुआ, तत्कालीन समय में चमत्कार हुआ और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल ले गए, जहाँ उनका पालन-पोषण नंद बाबा और यशोदा के सान्निध्य में हुआ।

बाल्यकाल से ही श्रीकृष्ण ने अपने अद्भुत स्वरूप और दैवीय लीलाओं से सबका मन मोह लिया। उनका माखन चोरी करना, बांसुरी बजाना और गोपियों संग रास रचना आज भी भक्तों को आनंदित करता है।

जन्माष्टमी की धार्मिक महत्ता

जन्माष्टमी केवल श्रीकृष्ण के जन्म की स्मृति मात्र नहीं है, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देने वाला पर्व है। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है - जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब-तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कंस जैसे दुष्ट का वध किया और महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना की।

इस दिन उपवास, रात्रि जागरण, भजन-कीर्तन, भागवत कथा और श्रीकृष्ण की झांकी का विशेष महत्व है। भक्त मानते हैं कि व्रत और भक्ति से भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं।

जन्माष्टमी की प्रमुख परंपराएँ

उपवास और रात्रि जागरण- भक्त इस दिन निर्जला अथवा फलाहारी उपवास रखते हैं और रात बारह बजे तक भजन-कीर्तन कर जागरण करते हैं।

झूला सजाना और झांकी-घरों और मंदिरों में झूले सजाए जाते हैं, जिनमें बाल गोपाल की प्रतिमा को झुलाया जाता है।

मूर्तियों का अभिषेक-आधी रात को कृष्ण जन्म के समय शिशु कृष्ण की मूर्ति का दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक किया जाता है।

दही हांडी-महाराष्ट्र में दही हांडी की परंपरा विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसमें गोविंदाओं की टोली मानव पिरामिड बनाकर ऊँचाई पर

लटकी मटकी तोड़ती है।

रासलीला और कृष्णलीला- मथुरा, वृंदावन और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में रासलीला का आयोजन होता है, जिसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है।

भारत में जन्माष्टमी के उत्सव

भारत के विभिन्न राज्यों में यह पर्व विविध रूपों में मनाया जाता है -

उत्तर प्रदेश

मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का आयोजन भव्यतम रूप में होता है। मंदिरों में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं और रासलीला की परंपरा विशेष आकर्षण होती है।

महाराष्ट्र

यहाँ गोकुलाष्टमी पर दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है, जहाँ युवा गोविंदा टोली बनाकर ऊँचाई पर रखी हांडी तोड़ते हैं।

गुजरात और राजस्थान

द्वारका और नाथद्वारा जैसे स्थानों पर विशेष पूजा और माखन हांडी उत्सव होते हैं।

पूर्वोत्तर भारत

असम और मणिपुर में शंकरदेव और चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव परंपरा के तहत भक्ति नृत्य और नाटक आयोजित होते हैं।

दक्षिण भारत

तमिलनाडु और केरल में घरों को कोलम और फूलों से सजाया जाता है, वहीं उडुपी और गुरुवायूर के कृष्ण मंदिरों में विशेष उत्सव होते हैं।

विदेशों में जन्माष्टमी

भारत के साथ-साथ नेपाल, बांग्लादेश, फिजी, अमेरिका, ब्रिटेन और कैरिबियन देशों में भी जन्माष्टमी बड़े उत्साह से मनाई जाती है। नेपाल में यह राष्ट्रीय पर्व है, वहीं फिजी में आठ दिनों तक भक्ति संगीत और भागवत कथा का आयोजन होता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में इस्कॉन मंदिरों द्वारा जन्माष्टमी विशेष धूमधाम से मनाई जाती है।

श्रीकृष्ण का सार्वभौमिक संदेश

भगवान कृष्ण केवल हिंदू आस्था के देवता नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के अद्वितीय शिक्षक भी हैं। उनकी गीता में दी गई शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि मनुष्य को केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।

श्रीकृष्ण प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं। उनका जीवन संदेश देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह सामाजिक एकता, प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश देने वाला पर्व है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में इस दिन भक्तगण बाल गोपाल के जन्म का उल्लास मनाते हैं। श्रीकृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि प्रेम, सत्य और धर्म ही मानवता की सच्ची शक्ति है।

अत: जन्माष्टमी का यह पावन पर्व हमें न केवल भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी दिव्यता का स्मरण कराता है, बल्कि हमें उनके उपदेशों को जीवन में अपनाकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है।

आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक का होना; जाने क्या कारण हो सकते हैं; बचने के उपाय ...

1. खराब जीवनशैली (Unhealthy Lifestyle)

- जंक फूड का सेवन- पैकेज्ड फूड, तैलीय खाना, अत्यधिक नमक और चीनी से भरपूर आहार दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा करता है।
- शारीरिक निष्क्रियता- लंबे समय तक बैठे रहना, स्क्रीन टाइम अधिक होना और व्यायाम की कमी मोटापा और हृदय रोग का बड़ा कारण है।

2. तनाव (Stress)

- लगातार मानसिक तनाव हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है।
- इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

3. धूम्रपान और शराब का सेवन (Smoking & Alcohol)

- धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को सख्त और संकीर्ण करता है।
- ज़ शराब का अत्यधिक सेवन ट्राइग्लिसराइड्स और ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है।

4. आनुवंशिक कारक (Genetic Factors)

- यदि परिवार में किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक या हृदय रोग हुआ हो, तो अगली पीढ़ी में भी यह जोखिम बढ़ जाता है।

5. अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ (Other Health Conditions)

- उच्च रक्तचाप - लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हृदय की मांसपेशियों को कमजोर करता है।
- मधुमेह - शुगर लेवल बढ़ने से धमनियों में नुकसान होता है।
- उच्च कोलेस्ट्रॉल- खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) धमनियों में चर्बी जमाता है, जिससे ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है।

बचाव के उपाय (Prevention Tips)

1. स्वस्थ आहार (Healthy Diet)

- रोज़ फल, हरी सब्जियाँ, दालें और साबुत अनाज खाएँ।
- फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और तैलीय भोजन को सीमित करें।
- पर्याप्त पानी पिएँ।

2. नियमित व्यायाम (Regular E&ercise)

- रोज़ाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या दौड़ें।
- तैराकी, साइक्लिंग, योग और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएँ।

3. तनाव प्रबंधन (Stress Management)

- मेडिटेशन, गहरी साँस लेने की तकनीक और पर्याप्त नींद से तनाव कम करें।
- अपने शौक और परिवार के साथ समय बिताएँ।

4. धूम्रपान और शराब से दूरी (Avoid Smoking & Alcohol)

- धूम्रपान तुरंत छोड़ें, यह हृदय स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी कदम है।
- शराब का सेवन न्यूनतम रखें या बिल्कुल न करें।

5. नियमित स्वास्थ्य जांच (Regular Health Check-ups)

- ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जाँच करवाएँ।
- समय-समय पर ईसीजी और डॉक्टर की सलाह लें।

युवाओं में हार्ट अटैक का बढ़ना केवल चिकित्सा की चुनौती नहीं है, बल्कि हमारी जीवनशैली की चेतावनी भी है। यदि हम सही खानपान, नियमित व्यायाम, तनाव नियंत्रण और नशे से दूरी जैसे छोटे-छोटे बदलाव करें, तो युवा पीढ़ी स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकती है।

सबका साथ-सबका विकास की संकल्पना को पूरा करने पूर्ण इच्छाशक्ति के साथ कार्य कर रही है प्रदेश सरकार-उद्योग मंत्री देवांगन

प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ''सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'' के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में प्रारंभ की गई अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था, किन्तु वर्तमान मुख्यमंत्री ने न केवल उन्हें पुनः शुरू कराया है बल्कि कई नई जनहितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया है, जिनका लाभ प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को प्राप्त हो रहा है।

श्री देवांगन कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र के बरपारा कोहड़िया में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 48 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्वसुविधायुक्त उद्यान का लोकार्पण किया। इस उद्यान का निर्माण नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा केंद्र सरकार की एन.सी.ए.पी. मद से कराया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने की। सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष श्री गोपाल मोदी, पार्षद नरेन्द्र देवांगन, वरिष्ठ पार्षद अशोक चावलानी सहित निगम की मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य, पार्षदगण और अनेक जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा के विकास को लेकर उनका संकल्प स्पष्ट है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नगर निगम कोरबा क्षेत्र के सभी 67 वार्डों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य किए जाएंगे। जन समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा -कोरबा की जनता मेरी अपनी है, मैं स्वयं को उनके परिवार का सदस्य मानता हूं। उनकी समस्याओं का समाधान और सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना मेरा प्रथम कर्तव्य है।

श्री देवांगन ने यह भी बताया कि कोरबा जिले में विकास कार्यों के लिए लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिन्हें मूर्त रूप देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से नगर निगम क्षेत्र को समस्यामुक्त बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कहा कि उद्योग मंत्री के प्रयासों से निगम क्षेत्र को निरंतर विकास कार्यों के लिए धनराशि प्राप्त हो रही है। इसी कारण निगम क्षेत्र में सड़कों, उद्यानों, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य निर्माण कार्यों को बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि निगम क्षेत्र में नागरिकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप ही योजनाओं का क्रियान्वयन होगा।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि कोरबा की जनता को अब विकास कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। सर्वसुविधायुक्त उद्यान का निर्माण न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय नागरिकों, विशेषकर स्लम बस्तियों के बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्यप्रद और मनोरंजन का बेहतर माध्यम सिद्ध होगा। इस प्रकार उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के सहयोग से कोरबा नगर निगम क्षेत्र में विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे नागरिकों में नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है।

सोयाबीन चिली बनाने कि आसान विधि ... (जी.वी.एस.रुक्मणी देवी)

सोयाबीन चिली कैसे बनाते है?

सोयाबीन चिली एक ऐसी डिश है जो सभी सो पसंद आती है क्योंकि स्पाइसी खाना किसे पसंद नहीं आती7 सोयाबीन चिली पौस्टिक चिझोन से भरपूर होता है । क्योंकि इसमें हम बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करते है । इसे आप रोटी चावल या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते है। सोयाबीन चिल्ली को आप 15-20 मिनट में बना सकते है । इसे आप ग्रेवी वाला या फिर ड्राई भी बना सकते है। तो चलिए देखते है कि सोयाबीन चिली कैसे बनाते है और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए...

सामग्री

सोयाबीन-	50 ग्राम
प्याज-	1
हरी मिर्च-	4
शिमला मिर्च-	1/2 पीस
हरी प्याज-	1/2
गाजर-	1
तेल-	100 ग्राम
ज़ीरा-	1 चम्मच
अंडा-	1
लहसुन अदरक पेस्ट-	2 चम्मच
काली मिर्च-	1/2चम्मच
मक्के का आटा-	2 चम्मच
नमक-	स्वाद अनुसार
सोया सॉस-	2 चम्मच
मिर्ची सॉस-	3 चम्मच
विनेगर-	2 चम्मच
धनिया पत्ता	

बनाने की विधि-

सबसे पहले पानी में थोड़ा सा नमक डाल दे और सोयाबीन को डाल कर उसे 2 मिनट उबाल ले और उसे ठंडा हने के लिए छोड़ दे ।अब प्याज, शिमला मिर्च , हरी प्याज और हरी मिर्च को छोटा छोटा काट ले । अब सोयाबीन को अब पानी से निचोड़ ले । फिर उसमे अंडा, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, काली मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, मक्के का आटा और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिलाये । फिर उसे तेल में अच्छे से फ्राई कर ले । फिर गैस पे पैन चढ़ाये, और उसमे तेल और जीरा डाले, फिर उसमे प्याज और गाजर को डाल के थोड़ी देर भुने । फिर उसमे शिमला मिर्च और थोड़ा नमक डाल कर थोड़ी देर भुने । फिर उसमे सोया सॉस, टमाटो सॉस और विनेगर डाल दे । उसके बाद सोयाबीन फ्राई को डाल दे और थोड़ा सा नमक डाल कर उसे अच्छे से मिलाये । और उसे ढककर 2 मिनट तक पकाये । अब उसमे धनिया पत्ता डालकर गैस को बंद कर दे । फिर उसे सर्विंग बॉउल में निकाल ले और और हमारी सोयाबीन चिली बन कर तैयार है ।

सुझाव:-

सोयाबीन को गरम पानी में डालकर फुला ले । अगर आप सोयाबीन में अंडा मिलाएंगे तो डालते समय सोयाबीन ज्यादा तेल नहीं सोखता है और टेस्ट भी अच्छा होता है । सोयाबीन को छानते समय तेल गरम होनी चाहिए और आंच मध्यम । आप चाहे तो आप अपनी पसंद की भी सब्जी भी डाल सकते है । तो यह थी हमारी आज की रेसिपी मुझे विश्वास है कि आप को यह बहुत पसंद आई होगी। अगर इस रेसिपी को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को जल्द से जल्द ख़त्म कर दूं। या अगर आप किसी और रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उसे जल्द से जल्द अपने अगले पोस्ट के जरिए आपको बता दूं।

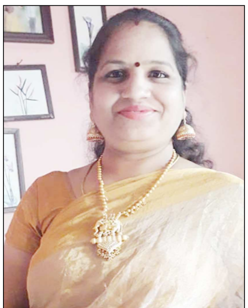

(जी.वी.एस.रुक्मणी देवी)

लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु कार्ययोजना बनाकर ग्रामीणों के आजिविका को बढ़ाये-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने बीते दिनों बीजापुर प्रवास के दौरान जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर कम्युनिटी पुलिसिंग सिविक एक्शन सहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं का व्यापक स्तर पर ि यान्वयन के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। नियद नेल्लानार क्षेत्रों में बिजली पानी सड़क स्कूल आंगनबाड़ी सहित मूलभूत सुविधाओं की पहुंच तथा वर्षों से वंचित ग्रामीणों को मूलभूत दस्तावेज सुलभ कराए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। परंपरागत व्यवसाय लघु वनोपज के उपलब्धता अनुसार संग्रहण प्रसंस्करण तथा व्यापक स्तर बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने विपणन हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाकर आर्थिक संवृद्धिकरण की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बने लखपति दीदी एवं स्व सहायता समूह की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। वहीं नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के रोजगार के अवसर और कौशल विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए नियमित रूप से आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने को कहा गया।नियद नेल्लानार क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैम्पों के समीप गांवों में पढ़ें लिखे युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण देकर अटल डिजिटल सुविधा केंद्र चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार को लेकर बैंक सखी, एटीएम सुविधा सहित नवीन बैंकों के स्थापना हेतु जिला स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिला प्रशासन द्वारा प्रतियोगी परीक्षा हेतु संचालित युवा कैरियर एकेडमी में अध्ययनरत सुदूर क्षेत्रों के युवाओं की आवासीय सुविधाओं की जानकारी ली।बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा, जिला पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा श्री नंदलाल मुड़ामी,सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री भीम सिंह, आयुक्त बस्तर संभाग श्री डोमन सिंह, आईजी बस्तर श्री सुंदरराज पी, डीआईजी श्री कमलोचन कश्यप कलेक्टर श्री संबित मिश्रा, डीएफओ श्री रंगानाथन रामाकृष्णा वाय, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे सहित वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष ने श्री रामलला दर्शन के लिए दुर्ग एवं बस्तर संभाग के 765 तीर्थ यात्रियों को किया रवाना

ढोल-मंजीरे की मंगल ध्वनि के साथ श्रद्धालुओं को अयोध्या के लिए किया गया विदा; मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय श्रवण कुमार बन कर श्रद्धालुओं को श्री रामलला दर्शन करने अयोध्या धाम भेज रहे

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज रेलवे स्टेशन राजनांदगांव से श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना अंतर्गत दुर्ग एवं बस्तर संभाग के 13 जिलों के 765 तीर्थ यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना अंतर्गत प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से जाने वाले दर्शनार्थियों में अभूतपूर्व खुशी दिखी। जयश्री राम के जयकारे के साथ ढोल-मंजीरे की मंगल ध्वनि के साथ श्रद्धालुओं को अयोध्या के लिए विदा किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय श्रवण कुमार बन कर श्रद्धालुओं को श्री रामलला दर्शन करने अयोध्या धाम भेज रहे.

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ विशेषकर दुर्ग एवं बस्तर संभाग के 765 तीर्थयात्री श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना के तहत श्री रामलला दर्शन के लिए आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम) के संपूर्ण सुविधायुक्त ट्रेन के माध्यम से अयोध्या जा रहे है। उन्होंने कहा कि हम सभी अधिकांशत, अपने परिवार एवं मित्रों को विदा करने रेलवे स्टेशन आते है, लेकिन आज पहली बार बुजुर्गों को विदा करने के लिए सामूहिक रूप से यहां आए हैं, जिसके लिए पुण्य के भागी होंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वे धार्मिक स्थलों में जाकर अपने ईष्ट देव के दर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि आज इस अभूतपूर्व क्षण में सभी दर्शनार्थियों के चेहरे पर प्रसन्नता एवं खुशी है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन का 6 करोड़ रूपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे यह रेलवे स्टेशन एक नया स्वरूप लेगा। उन्होंने तीर्थयात्रियों से बातचीत की तथा उन्हें सुखद यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी।

छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए सौभाग्य का दिन है। जहां हम राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से श्री रामलला के दर्शन हेतु श्रद्धालुगणों को रवाना कर रहे है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय श्रवण कुमार बन कर छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अनेक धार्मिक स्थलों का दर्शन और भ्रमण करने भेज रहे है। पहले रायपुर एवं दुर्ग रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होती थी, लेकिन आज पहली बार राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन से तीर्थ यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रभु श्रीराम का ननिहाल है। ऐसा संयोग है कि माता कौशल्या की भूमि तथा भांचा श्रीराम की भूमि अद्भुत है। छत्तीसगढ़वासियों को अयोध्या धाम भेजने की शुरूआत की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया तथा मनोबल बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया।

स्वतंत्रता दिवस विशेष

स्वतंत्रता से संविधान तक- भारत की लोकतांत्रिक यात्रा

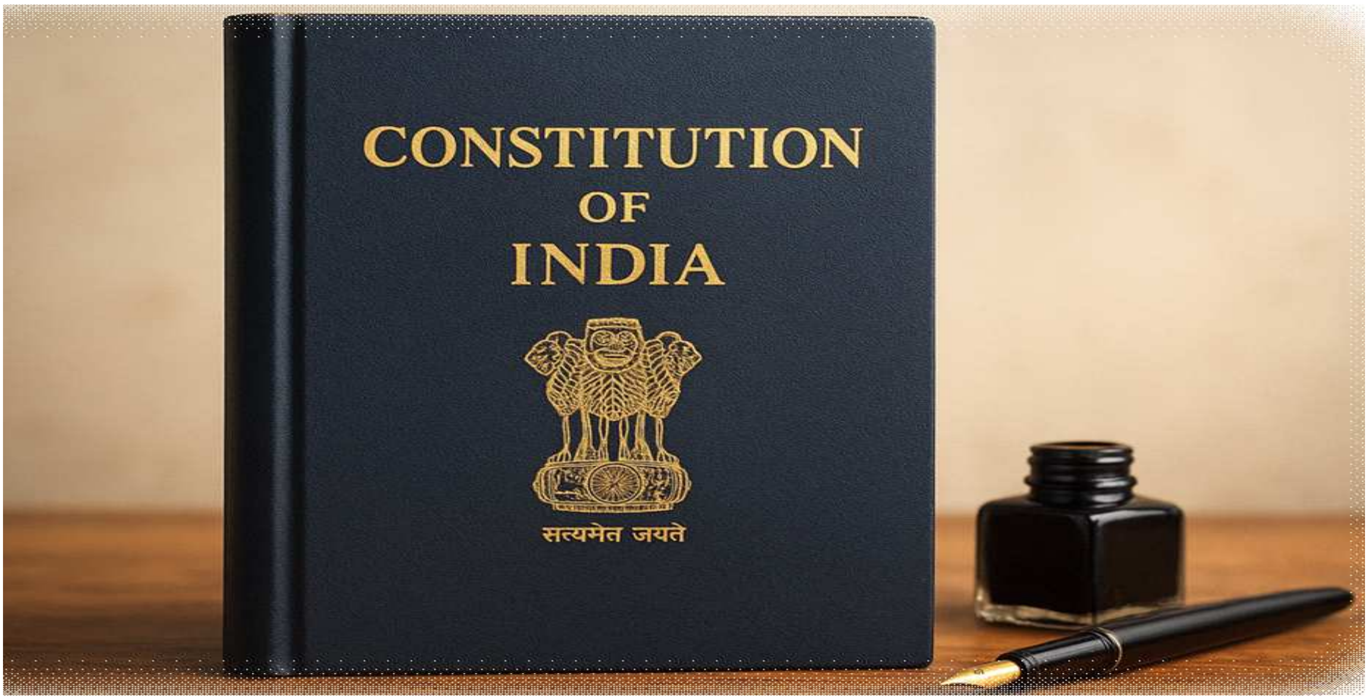

हर साल 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह दिन केवल राजनीतिक आज़ादी की याद नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है जिसने हमें लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, लेकिन आज़ाद भारत को दिशा देने के लिए एक ऐसे दस्तावेज़ की ज़रूरत थी, जो हमें न केवल शासन की राह दिखाए बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की भी गारंटी दे। यही दस्तावेज़ है ङ्क भारत का संविधान।

आज़ादी और संविधान का रिश्ता

स्वतंत्रता सेनानियों ने केवल अंग्रेज़ों से मुक्ति का सपना नहीं देखा था। उनका सपना था एक ऐसा भारत, जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, सामाजिक न्याय हो और नागरिकों को स्वतंत्रता का वास्तविक अनुभव हो।

- अगर 15 अगस्त 1947 ने हमें आज़ादी दी,
- तो 26 जनवरी 1950 ने उस आज़ादी को लोकतंत्र का स्वरूप दिया।

संविधान ने हमारी स्वतंत्रता को मज़बूती और स्थायित्व दिया।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया

संविधान निर्माण की शुरुआत 1946 में संविधान सभा के गठन से हुई।

- अध्यक्ष- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- मसौदा समिति के अध्यक्ष- डॉ. भीमराव अंबेडकर
- कुल समय- 2 साल 11 महीने 18 दिन
- कुल बैठकें- 165 से अधिक
- खर्च- लगभग 64 लाख
- अपनाया गया- 26 नवंबर 1949
- लागू हुआ- 26 जनवरी 1950

संविधान सभा में अनेक विचार-विमर्श, बहस और सुझावों के बाद यह दस्तावेज़ तैयार हुआ।

संविधान की विशेषताएँ

1. सबसे लंबा लिखित संविधान

भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रारंभिक रूप से इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। आज इसमें 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।

2. प्रस्तावना- संविधान की आत्मा

प्रस्तावना भारत को परिभाषित करती है-

हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए..

3. मौलिक अधिकार

नागरिकों के लिए छह मूल अधिकार निर्धारित किए गए हैं-

1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार

4. राज्य के नीति निर्देशक तत्व

ये सरकार को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देते हैं ङ्क जैसे सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर।

5. मौलिक कर्तव्य

42वें संशोधन (1976) द्वारा नागरिकों के 10 कर्तव्य जोड़े गए, जैसे राष्ट्र की एकता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आदि।

6. संघीय ढाँचा और एकात्मक प्रवृत्ति:

भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बाँटता है, परंतु संकट की स्थिति में केंद्र को अधिक अधिकार देता है।

7. धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र

संविधान हर धर्म को समान महत्व देता है और नागरिकों को अपने-अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है।

संविधान का महत्व

1. नागरिकों के लिए मार्गदर्शक- संविधान हर भारतीय के जीवन को दिशा देता है। यह बताता है कि हमें किन अधिकारों का आनंद लेना है और किन कर्तव्यों का पालन करना है।

2. लोकतंत्र की नींव- संविधान की बदौलत भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनावों से लेकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता तक ङ्क हर व्यवस्था संविधान से ही संचालित है।

3. स्वतंत्रता का संरक्षक- अगर 15 अगस्त ने हमें आज़ादी दिलाई, तो संविधान उस आज़ादी का संरक्षक बना। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक अन्याय का शिकार न हो।

स्वतंत्रता और संविधान - आज की प्रासंगिकता

आज जब हम 15 अगस्त मनाते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि- स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं, बल्कि कर्तव्यों का पालन भी है। संविधान हमें बताता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। आज़ादी को सही मायनों में जीना तभी संभव है जब हम संविधान के सिद्धांतों का पालन करें।

भारत का संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और लोकतंत्र की रीढ़ है। 15 अगस्त हमें स्वतंत्रता का गौरव याद दिलाता है, और संविधान हमें सिखाता है कि उस स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए कहा जा सकता है कि - आज़ादी ने हमें संविधान तक पहुँचाया और संविधान हमें आज़ादी को जीने की राह दिखाता है।

एशिया कप 2025- 9 सितंबर से यूएई में होगा आगाज़, भारत खिताब का प्रबल दावेदार...

क्रिकेट जगत की नजरें इस समय एशिया कप 2025 पर टिकी हुई हैं। टी-20 फॉर्मेट में होने वाला यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शुरू होगा। टीम इंडिया को इस बार खिताब का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को मेज़बान यूएई के खिलाफ खेलेगा।

इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार प्रमुख खेल नेटवर्क सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (एसपीएनआई) ने 2031 तक के लिए 17 करोड़ डॉलर में खरीदे हैं। इसके तहत सभी मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित होंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। विज्ञापन बाजार में भी इस टूर्नामेंट को लेकर जबरदस्त उत्साह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के मैचों में 10 सेकंड के विज्ञापन स्लॉट की कीमत 14 से 16 लाख रुपये तक तय की गई है।

टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हॉन्ग कॉन्ग की टीमें होंगी। फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा।

सबसे ज्यादा चर्चा भारत-पाकिस्तान मैच की है, जो 14 सितंबर को निर्धारित है। अगर दोनों टीमें सुपर-4 चरण में पहुंचीं, तो एक और हाई-वोल्टेज भिड़ंत देखने को मिल सकती है। क्रिकेट इतिहास में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों को सबसे ज्यादा दर्शक मिलते रहे हैं। 2023 एशिया कप के दौरान दोनों देशों के बीच हुए मैच को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 2.8 करोड़ दर्शकों ने एक साथ देखा था। ऐसे में इस बार भी नए रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है।

क्रिकेट प्रेमियों के लिए आने वाले हफ्ते बेहद रोमांचक रहने वाले हैं, क्योंकि इस एशिया कप में न केवल खिताबी जंग होगी बल्कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले से एक बार फिर क्रिकेट इतिहास का नया अध्याय लिखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग से युवाओं और महिलाओं को मिली नई दिशा.....

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य के चहुंमुखी विकास में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में राज्य के युवाओं को इस विकास में भागीदार बनाने युवा आयोग के माध्यम से अनेक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। युवा शक्ति-राष्ट्र की प्रगति इस विचार को साकार करने में छत्तीसगढ़ युवा आयोग एक प्रभावशाली कड़ी के रूप में उभरा है। प्रदेश के युवाओं को सशक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोग द्वारा कई अभिनव योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो न केवल उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी दे रही हैं।

छत्तीसगढ़ युवा आयोग की स्थापना युवाओं की समस्याओं के समाधान, मार्गदर्शन और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। आयोग का युवाओं को शिक्षा, स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ना, युवाओं के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना, युवा संवाद एवं भागीदारी के लिए मंच प्रदान करना, समाज सेवा, नेतृत्व और नवाचार को प्रोत्साहन देना मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग ने वर्ष 2025 में युवाओं, महिलाओं और खेल जगत के उत्थान के लिए अनेक सराहनीय कार्यक्रम आयोजित किए। इन पहलों से न केवल समाज में जागरूकता का प्रसार हुआ, बल्कि सकारात्मक बदलाव और नई ऊर्जा का संचार भी हुआ है।

युवा संवाद

राज्य भर के युवाओं को एक मंच पर लाकर उनके विचारों, समस्याओं और समाधान पर चर्चा के लिए 'युवा संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला, संभाग और राज्य स्तर पर आयोजित किये जाते हैं, जहाँ युवाओं को सरकारी नीतियों, योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। बस्तर संभाग के छह जिलोंकृबस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कोण्डागांव में 6 से 9 अप्रैल 2025 के बीच ''युवा संवाद कार्यक्रम'' का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी, युवा संगठन, एनएसएस व एनसीसी के कैडेट्स तथा खिलाड़ी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस कार्यक्रम ने युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को प्रबल किया गया।

युवा प्रेरणा शिविर, उद्यमिता और सम्मान

शिविरों के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, राष्ट्र सेवा की भावना और टीम वर्क का विकास किया जाता है। शिविरों में अनुशासन, योग, खेलकूद और जीवन जीने की कला की सीख दी जाती है। युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, इसमें महिला उद्यमियों और ग्रामीण युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को युवा गौरव और युवा प्रेरणा सम्मान से नवाजा जाता है, जिससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है।

डिजिटल युवा सशक्तिकरण एवं नवाचार

आईटी और डिजिटल स्किल्स के प्रशिक्षण के लिए विशेष कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इससे युवा डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा बन रहे हैं और रोज़गार की नई संभावनाओं से जुड़ रहे हैं।छत्तीसगढ़ युवा आयोग युवाओं को समाज सेवा से भी जोड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, ग्राम विकास, जल संरक्षण जैसे

विषयों पर विशेष युवा दल गठित कर कार्य करवाया जा रहा है। इससे युवाओं में समाज के प्रति दायित्व की भावना विकसित हो रही है।

छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न/2047

विकसित भारत/2047 और छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न/2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के युवा भी अपना योगदान दे सकें इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग प्रतिबद्धता से कार्यरत है।

महिला सम्मान और सशक्तिकरण

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को अंबिकापुर स्थित राजमोहिनी भवन में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण में योगदान को पहचान देने और उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण मंच बना। इसके अलावा 27 मई 2025 को रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जयंती के उपलक्ष्य में ''महिला सशक्तिकरण संवाद सम्मेलन'' का आयोजन किया गया। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर सार्थक चर्चा हुई और विजेताओं को सम्मानित किया गया।

योग और पर्यावरण-स्वास्थ्य का दोहरा लाभ

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर 21 जून 2025 को रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम (पिच-02) में ''योग संगम एवं हरित योग'' कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागियों को योगा मेट वितरित किए गए। इस अवसर पर योग भगाए रोग योगाभ्यास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर भी विशेष बल दिया गया।

खेल जागरूकता-दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए विशेष प्रयास

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 23 जून 2025 को रायपुर के एनएबी दृष्टिबाधित बालिका पुनर्वास केन्द्र ''प्रेरणा गुरूकुलम् विद्यापीठ'' में ''खेलों के प्रति जागरूकता अभियान'' आयोजित किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने बालिकाओं को पैरा ओलंपिक में भागीदारी के लिए प्रेरित किया और उन्हें खेल सामग्री भेंट कर प्रोत्साहित किया गया।

(आलेख द्वारा-श्री जयंत देवांगन, संयुक्त संचालक,
श्री विष्णु वर्मा, सहायक संचालक)

लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन और महिलाओं में हृदय रोग का बढ़ता खतरा..

हाल ही में कम्युनिकेशंस मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन (Chronic Inflammation) यानी लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन, महिलाओं में कमजोरी, सामाजिक असमानता और हृदय रोग (Cardiovascular Disease – CVD) के जोखिम से जुड़ी हुई है।

कैसे हुआ अध्ययन?

- 2,000 से अधिक महिलाओं (आयु 37-84 वर्ष) के ब्लड सैंपल लिए गए।
- इनमें 74 सूजन से जुड़े प्रोटीन की जांच की गई।
- लक्ष्य था यह समझना कि सूजन का संबंध कमजोरी, सामाजिक वंचना और हृदय रोग से कैसे है।

क्या निकले नतीजे?

- शोधकर्ताओं ने 10 प्रोटीन पहचाने, जो कमजोरी और सामाजिक वंचना से जुड़े पाए गए।
- इनमें से 4 प्रोटीन (TNFSFvy, HGF, CDCPv और CCLvv) का संबंध हृदय रोग के खतरे से भी निकला।
- खासकर CDCPv प्रोटीन, धमनियों के संकुचन या अवरोध जैसी गंभीर हृदय समस्याओं से जुड़ा पाया गया।

विशेषज्ञों की राय

डॉ. यू लिन (किंग्स कॉलेज लंदन)- ÷हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि सामाजिक तनाव और कमजोरी, सूजन के जरिए हृदय स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। यानी इनके बीच एक साझा जैविक मार्ग मौजूद है।÷

डॉ. क्रिस्टीना मेन्नी (मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी विशेषज्ञ)- कमजोरी, असमानता और हृदय रोग को पहले एक साथ देखा तो गया था, लेकिन जैविक लिंक स्पष्ट नहीं था। यह शोध बताता है कि सामाजिक तनाव से सूजन बढ़ सकती है और उसका असर सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है।

शोध का महत्व

- ये प्रोटीन बायोमार्कर्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि डॉक्टर यह पहचान सकें कि कौन-से लोग हृदय रोग के उच्च जोखिम में हैं।
- अगर निष्कर्ष और पुख्ता होते हैं तो-
- सूजन घटाने वाली थेरेपी को बढ़ावा मिलेगा।
- सामाजिक असमानता कम करने वाली नीतियों के जरिए भी स्वास्थ्य सुधार संभव होगा।

यह शोध इस बात को रेखांकित करता है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मेडिकल और सामाजिक नीति–दोनों का संतुलित प्रयास जरूरी है।

वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस धमाका- ट्रिनिटी रोशन ने फिर रचा नया इतिहास

भारतीय सिनेमा की दुनिया में बॉक्स ऑफिस पर सफलता का मतलब केवल पैसों की गिनती नहीं होता, बल्कि यह दर्शकों के विश्वास, कलाकार की मेहनत और फिल्म की लोकप्रियता का पैमाना भी होता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार ट्रिनिटी रोशन की नई फिल्म वॉर 2 ने रिलीज के केवल दो दिनों में ही यह साबित कर दिया है कि उनका नाम आज भी टिकट खिड़की पर सफलता की गारंटी है। दो दिनों में फिल्म ने ?108 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, और अब यह चर्चा का विषय बन गई है कि आने वाले हफ्तों में यह फिल्म कितने और रिकॉर्ड तोड़ेगी।

ट्रिनिटी रोशन की लोकप्रियता और फैन बेस

ट्रिनिटी रोशन आज के समय में बॉलीवुड के उन चुनिंदा सितारों में से हैं जिनकी फिल्में रिलीज होते ही एक इवेंट बन जाती हैं। उनका फिटनेस लेवल, डांसिंग स्टाइल और बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस उन्हें बाकी कलाकारों से अलग पहचान दिलाते हैं। यही कारण है कि उनकी हर नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जाता है।फिल्म वॉर 2 की घोषणा होते ही उनके फैंस में उत्साह साफ दिखाई देने लगा था। सोशल मीडिया पर फिल्म की चर्चा रिलीज से महीनों पहले ही शुरू हो गई थी। टिकटों की एडवांस बुकिंग ने भी यह साफ कर दिया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने वाली है।

रिलीज और शुरुआती प्रदर्शन

फिल्म वॉर 2 को 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने शानदार ओपनिंग करते हुए 51.50 करोड़ का कलेक्शन किया। यह आंकड़ा इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में से एक माना जा रहा है।

दूसरे दिन यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का लाभ फिल्म को पूरी तरह मिला। परिवारों और युवाओं की भारी भीड़ सिनेमाघरों में उमड़ी। नतीजा यह रहा कि दूसरे दिन फिल्म ने 56.50 करोड़ का कारोबार किया। इस तरह महज दो दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 108 करोड़ तक पहुंच गया।

बॉक्स ऑफिस आंकड़े

- पहला दिन (14 अगस्त)- 51.50 करोड़
- दूसरा दिन (15 अगस्त)- 56.50 करोड़
- दो दिन का कुल कलेक्शन- 108 करोड़

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो फिल्म पहले वीकेंड में ही 175-200 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है।

वर्ल्डवाइड बिज़नेस

वॉर 2 की सफलता केवल भारत तक सीमित नहीं रही। फिल्म को विदेशों में भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। अमेरिका, गल्फ देशों और यूरोप के बॉक्स ऑफिस से फिल्म को बेहतरीन कलेक्शन मिल रहे हैं। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन पहले ही हफ्ते में 200 करोड़ तक पहुंच सकता है।

यह साबित करता है कि ट्रिनिटी रोशन की लोकप्रियता केवल भारतीय दर्शकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग वैश्विक स्तर पर भी मजबूत है।

दर्शकों की प्रतिक्रियाएँ

फिल्म वॉर 2 को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएँ मिली-जुली रही हैं।

सकारात्मक पहलू

1. एक्शन सीक्वेंस- दर्शकों का मानना है कि फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसके धमाकेदार एक्शन सीन हैं।
2. रोशन की अदाकारी- रोशन ने अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय से हर फ्रेम में जान डाल दी।
3. संगीत और बैकग्राउंड स्कोर- गाने और म्यूजिक ने दर्शकों को प्रभावित किया।

नकारात्मक पहलू

1. कहानी- कुछ दर्शकों को लगा कि फिल्म की कहानी अपेक्षाकृत कमजोर है और एक्शन पर ही ज्यादा जोर दिया गया है।
2. स्क्रीनप्ले- कई जगहों पर फिल्म की गति धीमी होने की शिकायतें आईं।
3. भावनात्मक जुड़ाव- कुछ समीक्षकों का कहना है कि फिल्म में भावनाओं की गहराई की कमी है।

फिर भी, यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रिनिटी रोशन की स्टार पावर और फिल्म का भव्य निर्माण दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाने में सफल रहा।

स्वतंत्रता दिवस का लाभ

स्वतंत्रता दिवस हमेशा से बॉलीवुड फिल्मों के लिए खास अवसर रहा है। छुट्टी होने के कारण लोग परिवार और दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं। यही वजह रही कि वॉर 2 के दूसरे दिन का कलेक्शन पहले दिन से भी ज्यादा रहा।

यह ट्रेंड साबित करता है कि छुट्टियों और त्योहारों पर रिलीज़ होने वाली फिल्मों को हमेशा अतिरिक्त फायदा मिलता है।

फिल्म की खासियतें

1. हाई-ऑक्टेन एक्शन- फिल्म के एक्शन सीन्स को हॉलीवुड स्तर का बताया जा रहा है।
2. सिनेमैटोग्राफी- बड़े पैमाने पर शूट किए गए लोकेशन्स और कैमरा वर्क फिल्म को विजुअली शानदार बनाते हैं।
3. संगीत- फिल्म का म्यूजिक पहले ही युवाओं की जुबान पर चढ़ चुका था।
4. स्टार कास्ट- रोशन के साथ फिल्म में अन्य कलाकारों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया।

आगे की संभावनाएँ

ट्रेड पंडितों का मानना है कि आने वाले दिनों में फिल्म वॉर 2 और भी बड़े रिकॉर्ड बना सकती है। पहले वीकेंड के बाद भी अगर वर्ड-ऑफ-माउथ पॉज़िटिव रहा तो यह फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है।

अनुमान है कि फिल्म पहले हफ्ते में ही ?250 करोड़ वर्ल्डवाइड का आंकड़ा पार कर जाएगी। अगर अगले हफ्ते भी इसका प्रदर्शन मजबूत रहा तो यह आसानी से ?400ङ्ग500 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। वॉर 2 ने महज दो दिनों में ?108 करोड़ की कमाई कर बॉलीवुड को एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि ट्रिनिटी रोशन आज भी बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। भले ही फिल्म को समीक्षकों से मिले-जुले रिव्यू मिले हों, लेकिन दर्शकों का प्यार, स्वतंत्रता दिवस का फायदा और शानदार एक्शन सीक्वेंस ने इसे बॉक्स ऑफिस का चहेता बना दिया है।

एग्री स्टेक पोर्टल में भू-अभिलेख डेटा अपडेट न होने से किसान परेशान, फार्मर आईडी के लिए हो रही दिक्कतें...

छत्तीसगढ़ के किसानों को इस समय एग्री स्टेक पोर्टल की तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों किसान फार्मर आईडी के पंजीयन के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि अधिकांश गांवों में वर्ष 2022 के बाद से भू-अभिलेख संबंधी डेटा पोर्टल में अपडेट ही नहीं हुआ है। राजस्व विभाग के अंतर्गत भुइंया पोर्टल में जमीन संबंधी जानकारी अपडेट होने के बावजूद एग्री स्टेक पोर्टल पर पुराने रिकॉर्ड ही दिखाई दे रहे हैं। किसानों के लिए समस्या इसलिए और गंभीर हो गई है क्योंकि एग्री स्टेक पोर्टल में एक बार पंजीयन हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

पंजीयन नहीं तो समर्थन मूल्य व योजनाओं का लाभ भी नहीं

सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि किसानों का पंजीयन एग्री स्टेक पोर्टल में होने के बाद ही उन्हें फार्मर आईडी दी जाएगी। यही आईडी भविष्य में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय और कृषक उन्नति योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होगी। लेकिन भू-अभिलेख डेटा अपडेट नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में किसान पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं और अब तक इंतजार कर रहे हैं।

खरीफ 2025 के लिए डिजिटल फसल सर्वे

राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2025 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण शुरू करने की तैयारी की है। इसके लिए 15 अगस्त से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में सर्वे कराया जाएगा। यह कार्य जियो रेफ्रेंसिंग तकनीक के जरिए होगा, ताकि हर खेत का सटीक डेटा ऑनलाइन दर्ज हो सके।

हालांकि, प्रदेश के कुल 20,551 गांवों में से अभी तक केवल 14,560 गांवों का ही जियो रेफ्रेंस कार्य पूरा हुआ है। ऐसे में इस साल उन्हीं गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे संभव होगा। सर्वे के दौरान स्थानीय युवाओं के माध्यम से प्रत्येक खेत का जियो टैग फोटोग्राफ लेकर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

अब तक 25 लाख से अधिक फार्मर आईडी तैयार

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक राज्य में 25 लाख 7 हजार 740 किसानों की फार्मर आईडी तैयार हो चुकी है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए किसानों की फसल, उत्पादन, खाद-पानी की जरूरत और बाजार संबंधी जानकारी भी पोर्टल में दर्ज की जाएगी। इससे कृषि योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सटीक तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।

गांवों में सर्वेक्षक तैनात

डिजिटल सर्वे की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए हर गांव में प्रशिक्षित सर्वेक्षकों का चयन किया गया है। सर्वे ऐप के माध्यम से खेत की भौगोलिक स्थिति और फसल की फोटो रियल टाइम में अपलोड की जाएगी।

सीएससी में उपलब्ध फार्मर आईडी पंजीयन सुविधा

किसान आधार कार्ड, बी-1 खसरा जैसे दस्तावेजों के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (ष्टस्ष्ट) में जाकर फार्मर आईडी के लिए पंजीयन करा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा प्रति फार्मर आईडी के लिए सीएससी को 15 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। किसानों को इसके लिए किसी भी प्रकार की शुल्क राशि नहीं देनी होगी।

पारदर्शी आंकड़े और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन

कृषि विभाग का कहना है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का मुख्य उद्देश्य सटीक व पारदर्शी फसल आंकड़े जुटाना है। इससे न केवल योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा बल्कि किसानों को फसल ऋण, विशेषज्ञों की सलाह और बाजार उपलब्ध कराने में भी एग्री स्टेक पोर्टल मददगार साबित होगा।

तरस रहीं हिना खान, की खास अपील- कास्ट करने में झिझक रहे हैं...

कैंसर बीमारी की वजह से हिना खान को कई ऑफर छोड़ने पड़े, जिसके चलते वे काम में पिछड़ गई. अब वह पति पत्नी और पंगा के साथ छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं. उन्होंने फिल्ममेकर्स और टीवी शो निर्माताओं से खास अपील की है ।

टीवी स्टार हिना खान ने एक साल पहले अपने ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होने के बारे में बताया था. अब उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री के लोग उनके साथ काम करने में अभी भी संकोच कर रहे हैं ।एक्ट्रेस ने बताया कि बीमार होने के कारण उन्हें कई ऑफर छोड़ने पड़े. हालांकि अब वह %पति पत्नी और पंगा के साथ छोटे पर्दे पर लौट आई हैं. एक्ट्रेस ने कहा, यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है जब से यह सब हुआ. मैं काम करना चाहती हूं. किसी ने सीधे तौर पर मुझसे नहीं कहा कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं।

लेकिन मुझे लगता है कि लोग सही वजहों से झिझक रहे हैं. हिना खाने ने पीटीआई से कहा, %कोई बात नहीं, मुझे इस सोच को तोड़ना होगा. शायद इस शो से यह मुमकिन हो जाएगा, मैं इसे समझती हूं. अगर मैं उनकी जगह होती, तो मैं भी हजार बार सोचती. मैं ऑडिशन के लिए तैयार हूं, मैंने कहां रुकना है? पिछले एक साल से किसी ने मुझे कॉल नहीं किया. मैं सबके लिए तैयार हूं, प्लीज मुझे कॉल करें झ 3। साल की एक्ट्रेस ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी की 2, फियर फैक्टर- खतरों के खिलाड़ी 8 और बिग बॉस 11 जैसे शो के लिए मशहूर हैं.

उन्होंने कहा कि वह रियलिटी शो से काम पर वापसी करके खुश हैं, जो फिलहाल कलर्स चैनल पर प्रसारित हो रहा है। शो में हिना खान-रॉकी जायसवाल, देबिना बनर्जी-गुरमीत चौधरी, रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला, अविका गोर-मिलिंद चंदवानी, स्वरा भास्कर-फहद अहमद, गीता फोगाट-पवन कुमार और सुदेश लहरी-ममता लहरी जैसे सेलिब्रिटी कपल्स शामिल हैं.

जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Save Water
करें वर्षा जल संरक्षित ज़रूर,
जल की कमी भी होगी दूर।
वर्षा जल
संरक्षित
घर
जल पुन: उपयोग
प्रणाली

CSPDCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

सस्ती नहीं मुफ्त बिजली की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ संवाद आर.ओ.-13385/2

31 लाख परिवारों को मिल रहा हाफ बिजली बिल योजना का लाभ

15 लाख BPL परिवारों को **30 यूनिट फ्री + हाफ बिजली बिल** योजना का लाभ

डबल सब्सिडी केंद्र के साथ मिल रही राज्य की भी सब्सिडी

- हर महीने **200-360 यूनिट** तक बिजली उत्पादन
- बिजली बिल होगा **शून्य बची बिजली से होगी कमाई**

उपभोक्ता से बनें ऊर्जादाता

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना

मासिक बिजली बिल से भी कम ई.एम.आई. में लगाएं रूफ टॉप सोलर प्लांट

सोलर प्लांट क्षमता	केंद्र सरकार की सब्सिडी	राज्य सरकार की सब्सिडी	कुल सहायता राशि	आसान मासिक EMI
1 kW	₹30,000	₹15,000	₹45,000	₹167
2 kW	₹60,000	₹30,000	₹90,000	₹333
3 kW	₹78,000	₹30,000	₹1,08,000	₹800

*बैंक द्वारा 6% ब्याज दर पर आसान किश्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा (ई.एम.आई.) उपलब्ध

हमारा संकल्प
हाफ बिजली से मुफ्त बिजली

QR कोड स्कैन करें

आवेदन प्रक्रिया व अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं

https://pmsuryaghar.gov.in/